मनेन्द्रगढ़
26 जुलाई 2026 रविवार

दैनिक मीडियाऑडीटर

मनेन्द्रगढ़, रीवा एवं सतना से एक साथ प्रकाशित

शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा

● दीपके बोले- वे कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते ● लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए

नई दिल्ली,एजेंसी। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। NEET पेपर लीक केस में उनके इस्तीफे की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 36 दिन से जंतर-मंतर पर धरना दे रही है।

इस्तीफे के बाद जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा- वे कहते थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। प्रधान ने इस्तीफे को लेकर चिट्ठी पोस्ट की। दो पेज और 575 शब्दों में लिखी इस चिट्ठी में प्रधान ने बाकी बातों के साथ दो जगह युवाओं को भ्रमित करने की बात भी लिखी। चिट्ठी का यह हिस्सा नीचे हाइलाइट किया गया है।

सीजेपी बोली- कॉकरोच की जीत हुई : धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP ने कहा कि कॉकरोच की जीत हुई। जंतर-मंतर पर अभिजीत दीपके ने कहा- मंत्री का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन हमारी दो और मांगे हैं। हम ऐसे नहीं जाएंगे कॉकरोच एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है। जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनके परिवार को एक करोड़ मुआवजा मिले। पुलिस वालों पर एक्शन होना चाहिए। दिल्ली पुलिस अधिकारी याद रखें कॉकरोच से पंगा लिया है। हमने तो एक मंत्री का इस्तीफा ले लिया, तो तुम लोग क्या चीज हो। छात्रों पर केस वापस होने चाहिए। भैया ये लोकतंत्र है। मुझे एक महीने से लोग कहते थे क्या कर रहे हो कब तक बैठोगे। ये इस्तीफा नहीं देंगे। ये मनमानी सरकार है।

योगी बोले: नीट के दोषियों की संपत्तियां भी होंगी जब्त

संसद में पेपर लीक पर आएगा बिल

फतेहपुर,एजेंसी। फतेहपुर जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मदारीपुर कला स्थित मैदान में विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव का राजनीतिक संदेश देते हुए विकास को भाजपा की सबसे बड़ी ताकत बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले फतेहपुर आकांक्षी जिलों में गिना जाता था।

रोजगार, स्वास्थ्य और विकास के पैमानों पर जिला पिछड़ा हुआ था, लेकिन पिछले नौ वर्षों में तस्वीर बदली है और अब फतेहपुर आकांक्षी जिला नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले युवाओं की नौकरियों पर डकैती डाली जाती थी, जबकि आज पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं।

विकास कुछ क्षेत्रों तक सीमित था: उन्होंने मेडिकल कॉलेज, पुल, सड़क, बिजली, निवेश, अस्पताल और कंपोजिट विद्यालय जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने विकास को गांव-गांव तक पहुंचाया है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले विकास कुछ क्षेत्रों तक सीमित था और किसानों, युवाओं व आम जनता की उपेक्षा की जाती थी।

दोषियों की संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी: उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और सपा के शासन में युवाओं का शोषण हुआ और नकल माफिया को संरक्षण मिला।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर-मंतर पर जश्न

छात्रों ने छात्र एकता जिंदाबाद के नारे लगाए

» नीट पेपर लीक के बाद जान गंवाने वाले स्टूडेंट्स के लिए मौन रखा

नई दिल्ली,एजेंसी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर-मंतर पर जश्न का माहौल है। छात्रों ने छात्र एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान नीट पेपर लीक के बाद जान गंवाने स्टूडेंट्स के लिए मौन रखा। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा, क्या कह रहे थे, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। मंत्री का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन हमारी दो और मांगे हैं।' उन्होंने कहा, हम ऐसे नहीं जाएंगे कॉकरोच एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है। जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनके परिवार को एक करोड़ मुआवजा मिले। पुलिस वालों पर एक्शन होना चाहिए। दिल्ली पुलिस अधिकारी याद रखें कॉकरोच से पंगा लिया है।

अभिजीत ने कहा, 'हमनें तो एक मंत्री का इस्तीफा ले लिया तो तुम लोग क्या चीज हो। छात्रों पर केस वापस होने चाहिए। भईया ये लोकतंत्र है। मुझे एक महीने से लोग कहते थे क्या कर रहे हो कब तक बेठोगे। ये इस्तीफा नहीं देंगे। ये मनमानी सरकार है। मगर हमने कर दिखाया।'

दीपके ने कहा- कॉकरोच हैं, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है: कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा,'क्या कहते हैं थे। इस सरकार में इस्तीफा नहीं होते। हमने ले लिया। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।' इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी 2 और मांगें हैं। ऐसे ही नहीं जाएंगे। कॉकरोच हैं, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है। इस्तीफा हो गया है।

कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन खत्म करने का ऐलान, कहा- सरकार ने मान ली मांग

नई दिल्ली,एजेंसी। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने शनिवार को सरकार के साथ एक अहम बैठक की। बैठक के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया। सीजेपी ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी। वहीं, सीजेपी ने जंतर-मंतर से आंदोलन को वापस लेने का ऐलान करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने हमारी मांग मान ली है और हम आंदोलन को खत्म करने का ऐलान करते हैं।

सरकार से बातचीत के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि हमने सरकारी प्रतिनिधिमंडल के साथ तीन राउंड की बातचीत की। जंतर-मंतर पर हमारा प्रोटेस्ट, जो कई दिनों से चल रहा था, हमारी तीन मुख्य मांगें थीं: केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शनकारियों और आयोजकों के खिलाफ फाइल किए गए सभी लीगल केस, एफआईआर वापस ली जाएं और प्रदर्शनकारियों या आयोजकों के खिलाफ भविष्य में कोई केस फाइल नहीं किया जाए।सीजेपी ने कहा कि हमारी मांग थी कि नीट पेपर न होने के बाद जिन परिवारों ने अपनों को खो दिया, उन्हें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए।

वांगचुक बोले- ये लोकतंत्र की जीत

सोनम वांगचुक ने अस्पताल से किए पोस्ट में लिखा- यह लोकतंत्र की जीत है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र... सड़कों से मिली जीत। यह शांति, धैर्य और दृढ़ता की जीत है। छ्छ्क्कऔर त्द्दर्इ को बधाई। देश के हर कोने से उठ खड़े होने के लिए सभी नागरिकों को धन्यवाद।

: ब्रीफ बॉक्स :

भागवत बोले: नई पीढ़ी को आदेश न दें, बातचीत करें

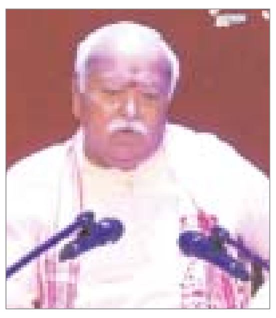

नई दिल्ली,एजेंसी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को दिल्ली में कहा, 'आज की नई पीढ़ी बहुत सारे सवाल पूछती है। हमें आदेश देने की बजाय उनसे बातचीत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें हर बात के पीछे का तर्क समझाना चाहिए, न कि आदेश देना चाहिए। संवाद के जरिए ही उन्हें सही दिशा दिखाई जा सकती है। हम मनमानी करेंगे, शक्ति से सबके मालिक बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब देश में पेपर लीक के मुद्दे को लेकर छात्र जंतर-मंतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

पहले माता-पिता की बात ही अंतिम होती थी, लेकिन आज नहीं: मोहन भागवत ने कहा, 'पहले के समय में माता-पिता की बात बिना किसी सवाल के मान ली जाती थी। जब हम छोटे थे, तो माता-पिता जो कहते थे, वही अंतिम होता था।' कोई बहस नहीं होती थी। श्रद्धा थी और प्रतिक्रिया भी नहीं होती थी, लेकिन अब समय बदल गया है। नई पीढ़ी सवाल पूछती है और उन्हें हर बात का तर्क बताना पड़ता है। नई पीढ़ी को बहुत अपनापन देने की जरूरत है, उन्हें समय देने की जरूरत है और सबसे ज्यादा संवाद की जरूरत है। आज डिक्टेशन नहीं, डिस्कशन की जरूरत है। ऑर्डर नहीं, कॉन्शसनेस (जागरूकता) की जरूरत है।

गुजरात में भारी बारिश, 5 की मौत

असम में बाढ़ से 24 घंटे में 14 मौतें

म.प्र.- यूपी, राजस्थान में बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली/ भोपाल/ जयपुर, एजेंसी। गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश से कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों से 40,500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। बारिश से जुड़े हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई है। अहमदाबाद में आज सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। असम में बाढ़ से पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 61 हो गई है। राज्य के 12 जिलों में बाढ़ से 7.05 लाख से ज्यादा लोग

प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश का स्ट्रॉग सिस्टम एक्टिव है, जिसके चलते आज प्रदेश के 35 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

उत्तर प्रदेश में पिछले 15 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इसे देखते हुए शनिवार को राज्य के 30 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इधर, राजस्थान में भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने शनिवार को राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिए ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है। अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद शनिवार को फिर से शुरू हो गई।

भारत ने स्वदेशी काउंटर-ड्रोन सिस्टम 'भार्गवास्त्र' का ट्रायल

● सेना के कयुनिकेशन नेटवर्क से जुड़ सकता है ● ड्रोन के झुंड को रोक सकता है

नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय सेना के सामने सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड (SDAL) ने नागपुर में अपने स्वदेशी काउंटर-ड्रोन सिस्टम 'भार्गवास्त्र' का सफल लाइव ट्रायल किया। कंपनी का दावा है कि यह सिस्टम हवाई हमलों और ड्रोन स्वार्म (ड्रोन के झुंड) जैसे बढ़ते खतरों से निपटने के लिए तैयार है। इसे सेना के कमांड और कम्युनिकेशन नेटवर्क C4I से भी जोड़ा जा सकता है।

मौजूदा जानकारी के मुताबिक, यह सिस्टम खतरनाक ड्रोन और खुद से उड़ने वाले ड्रोन के झुंड को रोकने के लिए बनाया गया है। इनपुट में ट्रायल की तारीख और सेना की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया की जानकारी नहीं दी गई है। यह जानकारी अभी सामने नहीं आई है। कंपनी के मुताबिक ट्रायल सफल रहा।

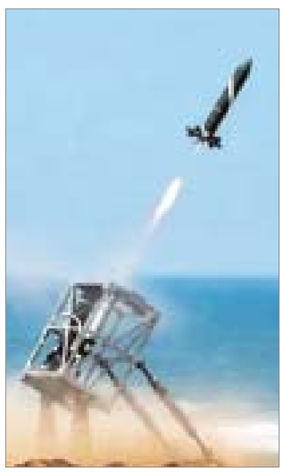

गाड़ी पर लगने वाला मोबाइल सिस्टम: भार्गवास्त्र को गाड़ी पर आसानी से लगाया जा सकता है। इससे जरूरत पड़ने पर इसे तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर तैनात किया जा सकता है। कंपनी का कहना है कि इससे अलग-अलग इलाकों में तुरंत ऑपरेशन करना आसान होगा।

रेगिस्तान से 5,000 मीटर ऊंचे पहाड़ तक तैनाती... कंपनी के अनुसार, भार्गवास्त्र को रेगिस्तान, मैदान और समुद्र तल से 5,000 मीटर तक ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भी तैनात किया जा सकता है। इसे अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियों में इस्तेमाल करने के हिसाब से तैयार किया गया है।

10 किमी तक ड्रोन का पता लगाने की क्षमता... सिस्टम के कंट्रोल सेंटर में 10 किमी तक ड्रोन का पता लगाने वाला रडार और खास सेंसर लगाए गए हैं। कंपनी के मुताबिक ये सेंसर लक्ष्य की पहचान कर उसे ट्रैक करने में मदद करते हैं, जिससे ड्रोन के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

स्वदेशी रॉकेट और माइक्रो-मिसाइल से लैस: कंपनी के मुताबिक, इस सिस्टम में देश में बने रॉकेट और सटीक निशाना लगाने वाली माइक्रो-मिसाइल लगी हैं। दावा है कि ये दुश्मन के ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर सकती हैं।

ट्रम्प बोले- चीन-रूस जंग में आए तो अंजाम बुरा होगा

पुतिन-जिनपिंग ने मुझे यकीन दिलाया, वे ईरान को हथियार नहीं देंगे

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी,एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें नहीं लगता कि चीन या रूस ईरान युद्ध में शामिल हैं। हालांकि उन्होंने धमकी दी कि अगर दोनों देशों ने इस युद्ध में दखल दिया तो इसके गंभीर नतीजे होंगे और यह उनके लिए अच्छा नहीं होगा।

ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हाल ही में बीजिंग में हुई उनकी मुलाकात के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें भरोसा दिया था कि वे किसी भी हाल में ईरान को हथियार नहीं देंगे। चीनी कंपनियों के लिए भी यही चीज लागू है।

ट्रम्प ने कहा मुझे जिनपिंग पर यकीन है। उन्होंने यह भी कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी उनसे कहा था कि वे ईरान को हथियार नहीं बेचेंगे। ट्रम्प ने कहा कि यूक्रेन जंग के बावजूद उनकी पुतिन से बातचीत जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका सीधे यूक्रेन को हथियार नहीं बेचता, बल्कि नाटो देशों को बेचता है। नाटो देश इन हथियारों की पूरी कीमत चुकाते हैं। उसके बाद वे इन्हें किस तरह आगे भेजते हैं, इसकी उन्हें जानकारी नहीं होती।

अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, ईरान ने अपने कुछ सेंट्रीफ्यूज मशीन देश के मध्य हिस्से में स्थित बेहद सुरक्षित भूमिगत परिसर 'पिकएक्स माउंटेन' में पहुंचा दिए हैं। यह मशीन परमाणु संवर्धन के लिए इस्तेमाल होती है। इससे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी रिपोर्ट दी थी कि इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने इन सेंट्रीफ्यूज की आवाजाही पर नजर रखी थी।

रिपोर्ट- ईरान के नए सुप्रीम लीडर परमाणु हथियार के पक्ष में... न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुजतबा खामेनेई अपने पिता और पूर्व सुप्रीम लीडर के मुकाबले परमाणु हथियार बनाने के ज्यादा समर्थक हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को दोबारा शुरू कर दिया है। हालांकि, पिछले साल हुए अमेरिकी हमलों और मौजूदा जंग के दौरान मिले विराम के समय ईरान ने अपने परमाणु संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ कदम जरूर उठाए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा

सिर्फ पुरुष और महिला श्रेणी में ट्रांसजेंडरों की नियुक्ति कैसे होगी

» भर्ती में तीसरे लिंग की जगह कहां है

नई दिल्ली,एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के रोजगार अधिकारों को लेकर दिल्ली सरकार से पूछा कि जब सरकारी भर्ती विज्ञापनों में रिक्तियां केवल पुरुष और महिला श्रेणी में बांटी जाती हैं, तो ट्रांसजेंडरों की नियुक्ति कैसे होगी। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि सिर्फ आवेदन पोर्टल में थर्ड जेंडर का विकल्प जोड़ना इस समस्या का समाधान नहीं है। अदालत ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित करना भी जरूरी है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आवेदन पोर्टल में तीसरे लिंग का विकल्प जोड़ दिया गया है और याचिकाकर्ता आवेदन कर चुकी हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडरों को आरक्षण देने का फैसला न्यायिक आदेश से नहीं, बल्कि विधायिका के स्तर पर किया जा सकता है।

कोर्ट बोला- वे भी इंसान हैं, सहानुभूति से देखें... याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि शिक्षकों की भर्ती समेत कई सरकारी विज्ञापनों में अब भी पद 'पीजीटी बायोलॉजी (महिला)' और 'पीजीटी केमिस्ट्री (पुरुष)' जैसी श्रेणियों में बांटे जाते हैं। इस पर पीठ ने कहा, 'वे भी इंसान हैं, उन्हें सहानुभूति से देखें।' कोर्ट ने यह भी कहा कि आवेदन करने के बाद भी ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को यह कहकर बाहर किया जा सकता है कि वे तय श्रेणी में फिट नहीं बैठते। इसी मुद्दे पर अदालत ने दिल्ली सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। इनपुट में अगली सुनवाई की तारीख की जानकारी नहीं दी गई है।

सिंधिया संपत्ति विवादः 78 साल पुराने कोवेनेंट पर टिकी निगाहें, ऊटी से मुंबई तक फैली है जागीर

ग्वालियर, एजेंसी। सिंधिया राजघराने के बहुचर्चित संपत्ति विवाद में 78 वर्ष पुराना द कोवेनेंट (अनुबंध) दस्तावेज फिर केंद्र में आ गया है। 1948 में जब ग्वालियर, इंदौर और मालवा की रियासतों को मिलाकर संयुक्त राज्य मध्य भारत का गठन इसी कोवेनेंट के आधार पर किया गया था। इस अनुबंध में तत्कालीन शासकों की परिषद के गठन का प्रविधान किया गया। इसके प्रथम राजप्रमुख ग्वालियर के महाराजा को और वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंदौर के महाराजा को बनाया गया। अब यही ऐतिहासिक दस्तावेज अदालत में यह तय करने के लिए अहम माना जा रहा है कि सिंधिया राजघराने का किन संपत्तियों पर निजी स्वामित्व रह गया था और कौन-सी संपत्तियां मध्य भारत के गठन में राज्य को हस्तांतरित की गई थीं। ग्वालियर जिला न्यायालय में लंबित संपत्ति विवाद के निस्तारण के लिए 28 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में यह कोवेनेंट महत्वपूर्ण आधार बनेगा। दरअसल, कुछ संपत्तियां ऐसी हैं, जिनका बंटवारा सिंधिया राजपरिवार के उत्तराधिकारियों के बीच अभी भी विवाद का कारण बना हुआ है। इन पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी बुआ राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री यशोधरा राजे समेत परिवार के कई सदस्य अपना दावा कर चुके हैं। ऐसे में इस कोवेनेंट के आधार पर अदालत यह देखेगी कि सिंधिया राजपरिवार के पास मध्य भारत के गठन के समय कौन-कौन सी निजी संपत्तियां रह गई थीं। बता दें कि मध्य भारत राज्य के गठन के लिए तैयार किए गए इस कोवेनेंट पर ग्वालियर के तत्कालीन महाराजा जीवाजीराव सिंधिया, इंदौर के महाराजा यशवंतराव होलकर, धार के महाराजा आनंदराव पवार, अलीराजपुर के महाराजा सुरेंद्र सिंह, बड़वानी के राणा देवी सिंह तथा भारत सरकार के रियासत मंत्रालय के सचिव वीपी मेनन ने हस्ताक्षर किए थे। दस्तावेज में यह स्पष्ट किया गया था कि कौन-सी संपत्तियां शासकों की निजी रहेंगी और कौन-सी नई सरकार को हस्तांतरित की जाएंगी।

ऊटी से काशी और गोवा तक का जिक्र- कोवेनेंट में जीवाजीराव सिंधिया की निजी संपत्तियों का विस्तृत उल्लेख है। इनमें ग्वालियर के अलावा काशी का गंगा महल, ऊटी के कई लाज और बंगले, गोवा की संपत्तियां तथा मुंबई के दादर, धोबी तालाब, गवालिया टैंक रोड और वर्ली स्थित प्रसिद्ध समुद्र महल भी शामिल हैं। दरअसल, यही संपत्तियां वर्तमान विवाद में प्रमुख विषय बनी हुई हैं।मंदिर और छतरियों का भी उल्लेख-दस्तावेज में सिंधिया राजवंश से जुड़े धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का भी उल्लेख किया गया है। इनमें छतरी बाजार स्थित शाही छतरियां, विठ्ठल मंदिर, कोटेश्वर, भूतेश्वर मंदिर, उज्जैन के द्वारकाधीश और मदनमोहन मंदिर तथा काशी स्थित गंगा महल के प्रबंधन का अधिकार राजपरिवार के पास रहने का उल्लेख मिलता है। सरकार को सौंपी गई थीं ये संपत्तियां-कोवेनेंट के तहत सार्वजनिक उपयोग के लिए कई महत्वपूर्ण अचल संपत्तियां तत्कालीन मध्य भारत सरकार को सौंपी गई थीं। इनमें मोती महल पैलेस, गोरखी पैलेस, सरस्वती महल, जल विहार, गेंदघर, तिघरा कोठी, ग्वालियर किले की गद्दी बैरक, भदैया कुंड और शिवपुरी का फूलबाग शामिल हैं।

फास्ट ट्रैक कोर्ट की रफ्तार पड़ी धीमी, 2025 में 775 अदालतों ने निपटाए 66500 मामले

नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत 775 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों ने 2025 में 66,500 मामलों का निपटारा किया, जबकि पिछले साल के अंत में 2.45 लाख मामले लंबित थे। इन फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों में यौन अपराधों से बच्चों के बचाव के लिए बने कानून पोक्सो से संबंधित 398 अदालत शामिल हैं। कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों ने 2024 में 85,595 मामलों और 2023 में 76,319 मामलों का निपटारा किया था।

2019 में हुई थी शुरुआतः मंत्री ने कहा कि दुष्कर्म और पोक्सो के तहत अपराधों से जुड़े लंबित मामलों की तेजी से सुनवाई और निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाने की योजना 2019 में शुरू की गई थी। 790 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें स्थापित करने की इस योजना को 30 सितंबर, 2026 तक बढ़ाया गया है। मंत्री ने जिला और अधीनस्थ अदालतों के लिए बुनियादी ढांचे की सुविधाओं की एक और केंद्र-प्रायोजित योजना के बारे में भी जानकारी दी। इस योजना के तहत, 1993-94 से केंद्र और राज्यों के बीच तय फंड-शेयरिंग के आधार पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

दिल्ली में फिर 18 मेट्रो स्टेशन बंद, सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

नई दिल्ली, एजेंसी। राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन को लेकर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने शनिवार को भी 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने का फैसला लिया है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने भी सुरक्षा और बढ़ा दी है। वहीं, सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पुलिस के निर्देशों पर शुक्रवार को तीसरे दिन भी डीएमआरसी ने 18 प्रमुख मेट्रो स्टेशन बंद रखे थे। सुबह लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय सहित 17 मेट्रो स्टेशन बंद थे, लेकिन दोपहर में डेढ़ बजे अचानक न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन का भी गेट बंद कर दिया गया। साथ ही नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन के अंदर इंटरचेंज की सुविधा भी बंद कर दी गई।

यात्रियों को हो रही परेशानीः इसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों की चिंता बढ़ गई। स्टेशनों के बाहर खड़े लोग सुरक्षा कर्मियों से सवाल करते रहे। इसके बाद विभिन्न बस स्टॉपों पर यात्रियों की भारी भीड़ लगने लगी। बुधवार को 16, बृहस्पतिवार को 17 और शुक्रवार को 18 मेट्रो स्टेशन बंद रहे। आज भी यही 18 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे।

20 मिनट पहले मिली सूचनाः मालवीय नगर मेट्रो से आ रहे अर्जुन पांडे ने कहा कि उन्हें चेन्नई की फ्लाइट पकड़नी है। लेकिन नई दिल्ली मेट्रो और इंटरचेंज के बंद होने की सूचना 20 मिनट पहले ही मिली है। वह अब लक्ष्मी नगर मेट्रो उतरे हैं, लेकिन अब कैब बुक नहीं कर पा रहे हैं। क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है।

परिवार के लिए रोटी का इंतजाम कैसे करेंगेः गाजियाबाद से पहुंचे श्रमिक अमित कुमार पटेल चौक स्टेशन के बाहर सुरक्षाकर्मियों से सवाल पूछते दिखे कि जब मेट्रो बंद रहेगी तो वे अपने परिवार के लिए रोटी का इंतजाम कैसे करेंगे हालांकि, शाम को पांच बजकर 28 मिनट पर मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के गेट खोल दिए गए। उधर, चालू मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर छात्र पैदल ही लंबा सफर तय करके जंतर मंतर की ओर जाते दिखे। मिंटो ब्रिज के पास तो पैदल जा रहे छात्रों के बीच अचानक बापू के वेश में एक व्यक्ति साथ चलने लगा तो छात्रों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। बंद मेट्रो स्टेशनों की लिस्ट लोक कल्याण मार्ग राजीव चौक पटेल चौक रामकृष्ण आश्रम मार्ग बाराखंबा रोड सुप्रीम कोर्ट सेवा तीर्थ जनपथ मंडी हाउस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आईटीओ दिल्ली गेट इंद्रप्रस्था खान मार्केट जोर बाग शिवाजी स्टेडियम झंडेवालान न्यू दिल्ली।

देहरादून भी बनेगा 'कोपेनहेगन' यूरोपीय शहरों जैसी सोच से बदलेगी उत्तराखंड की राजधानी की तस्वीर

देहरादून, एजेंसी। कल्पना कीजिए... सुबह का देहरादून, जहां राजपुर रोड से लेकर आइएसबीटी व मोहकमपुर तक लोग कारों की कतार में नहीं, बल्कि सुरक्षित साइकिल ट्रैक पर सफर कर रहे हों। हर 300 मीटर पर एक पार्क, सार्वजनिक बसें इतनी सुविधाजनक हों कि निजी वाहन निकालने की जरूरत ही न पड़े और शहर का विकास सीमेंट-कंक्रीट नहीं, बल्कि नागरिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण से मापा जाए। यही तस्वीर महायोजना-2041 के लिए पिछले दिनों हुई जनसुनवाई के दौरान विभिन्न संगठनों व आमजन ने सुझाई है।

एक अलग बहस छेड़ीः महायोजना पर अंतिम दौर की जनसुनवाई के बीच दूनवासियों ने एक अलग बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि क्या देहरादून का विकास पुराने फार्मूले 'सड़क चौड़ी करो, फ्लाईओवर बनाओ' पर होगा या फिर कोपेनहेगन, एम्स्टर्डम और वियना जैसे शहरों की तरह लोगों को केंद्र में रखकर

क्या बन पाएगा 'सपनों का शहर' दूनः दून की सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि शहर बढ़ रहा है, बल्कि यह है कि शहर किस दिशा में बढ़ रहा है। अगर महायोजना-2041 भी केवल भवनों, सड़कों और प्लाटों तक सीमित रह गई।

हिमाचल में दुर्लभ नजारा, किन्नौर में 3400 मीटर की ऊंचाई पर पहली बार दिखा पीले पैरों वाला हरा कबूतर

शिमला, एजेंसी। किन्नौर जिला के रक्छम-छितकुल वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार पीले पैरों वाला हरा कबूतर (येलो-फुटेड ग्रीन पिजन) देखा गया है। यह दुर्लभ पक्षी लगभग 3,400 मीटर की ऊंचाई पर दर्ज किया गया, जो हिमाचल में इस प्रजाति का अब तक का सबसे ऊंचाई वाला आधिकारिक रिकॉर्ड माना जा रहा है। इसके साथ ही यह किन्नौर जिले में इस प्रजाति की पहली पुष्ट उपस्थिति भी है। इस दुर्लभ पक्षी का अवलोकन और दस्तावेजीकरण ब्लाक वन अधिकारी संतोष कुमार ठाकुर और वन मित्र अल्पना नेगी ने रक्छम क्षेत्र में किया। इस रिकॉर्ड को सत्यापन के लिए राज्य के पक्षी विशेषज्ञों और पक्षी विज्ञान समुदाय को भेजा गया है। विशेषज्ञों के अनुसार पीले पैरों वाला हरा कबूतर सामान्यतः मैदानी क्षेत्रों, पहाड़ियों की तलहटी, बाग-बगीचों और लगभग 2,400 मीटर तक की ऊंचाई वाले वनों में पाया जाता है। यह प्रजाति आमतौर पर हिमालय के अधिक ऊंचे और ठंडे क्षेत्रों से दूर रहती है। ऐसे में बास्पा घाटी के निकट 3,400 मीटर की ऊंचाई पर इसका मिलना बेहद असाधारण और वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हिमाचल के प्रकृतिविद हिमांशु चौधरी ने बताया कि यह प्रदेश में इस प्रजाति का सबसे ऊंचाई वाला रिकॉर्ड माना जा रहा है। उन्होंने वर्ष 2020 में लद्दाख के माथो गांव में लगभग 3,500 मीटर की ऊंचाई पर दर्ज हुए एक दुर्लभ रिकॉर्ड का भी उल्लेख किया, जो ई-बर्ड मंच पर दर्ज है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के रिकॉर्ड पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के आवास में हो रहे बदलावों की ओर संकेत कर सकते हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि इसे जलवायु परिवर्तन या स्थायी विस्तार का प्रमाण मानने से पहले लंबे समय तक वैज्ञानिक निगरानी और अध्ययन आवश्यक होंगे। सराहन वन्यजीव प्रभाग के उप वन संरक्षक (डीसीएफ) अशोक नेगी ने कहा कि किन्नौर की जैव विविधता बेहद समृद्ध है और क्षेत्र में तैनात वन अधिकारियों की सक्रिय निगरानी के कारण लगातार नई पक्षी प्रजातियों का दस्तावेजीकरण हो रहा है। किन्नौर के उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा ने वन्यजीव विंग की टीम को बधाई देते हुए विश्वास जताया कि भविष्य में भी किन्नौर की पक्षी विविधता से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड सामने आते रहेंगे।

पेयजल परियोजनाओं में गड़बड़ी पर बंगाल सरकार सख्त, 15 दिन में एफआइआर और गिरफ्तारी की चेतावनी

कोलकाता, एजेंसी। बंगाल के जनस्वास्थ्य व अभियांत्रिकी (पीएचईडी) मंत्री डॉ अजय पोद्दार ने पेयजल परियोजनाओं में किसी भी तरह की अनियमितता पर जीरो टालरेंस नीति अपनाने का शुक्रवार को विधानसभा में ऐलान करते हुए दोषियों के खिलाफ 15 दिनों के भीतर एफआइआर दर्ज कर गिरफ्तारी की चेतावनी दी। पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान पेयजल परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मंत्री ने स्पष्ट कहा कि भ्रष्टाचार या लापरवाही में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। विधानसभा में पीएचईडी विभाग के बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने दिसंबर, 2028 तक जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने का काम पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने जोर दिया कि हर हाल में इस समयसीमा तक इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। मंत्री ने भूजल पर बढ़ती निर्भरता कम करने और सतही जल के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया।

पोद्दार ने कहा कि बीरभूम जिले में छह छोटी नदियां हैं और वहां कई चेक डैम बनाकर वर्षा जल का संरक्षण किया जा सकता है। उन्होंने गुजरात के नर्मदा माडल का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि सूखा प्रभावित क्षेत्रों को चेक डैम के जरिए जल से समृद्ध बनाया जा सकता है, तो उपजाऊ बंगाल में भी यह माडल सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है, जहां पानी का पर्याप्त भंडार है। पेयजल परियोजनाओं की प्रगति की स्वतंत्र निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मंत्री ने घोषणा की कि राज्य के प्रत्येक विधायक को अगले पांच दिनों के भीतर उनके विधानसभा क्षेत्र की सभी पीएचई परियोजनाओं की कंप्यूटरीकृत रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने विधायकों से इन परियोजनाओं की जमीनी स्थिति का मूल्यांकन करने का आग्रह किया और कहा कि वह स्वयं अधिकारियों के साथ सभी जिलों का दौरा करेंगे। पोद्दार ने चेतावनी देते हुए कहा कि जहां भी काम में गड़बड़ी या गुणवत्ता में कमी पाई जाएगी, वहां संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि 15 दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिन अधिकारियों ने ऐसे कार्यों के बिल पास किए हैं, उन्हें भी निलंबित किया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

ट्रंप ने न्यूक्लियर डील के बदले रखी अब्राहम समझौते की शर्त

सऊदी पर दबाव बना रहे अमेरिकी राष्ट्रपति

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक बार फिर कहा कि नागरिक परमाणु समझौते को अंतिम रूप देने के लिए सऊदी अरब को अब्राहम समझौते में शामिल होना होगा। उन्होंने कहा कि यह शर्त पूरी करना जरूरी है। ट्रंप ने कहा कि अब रियाद के पास ईरान जैसी क्षेत्रीय ताकत के दबदबे का खतरा नहीं है, इसलिए अब पीछे हटने की कोई वजह नहीं है।

अब्राहम समझौते क्या हैं: अब्राहम समझौते साल 2020 में अमेरिका की पहल पर हुए कई कूटनीतिक समझौतों का समूह है। इसके तहत इस्राइल और कई अरब देशों के बीच औपचारिक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध स्थापित हुए थे। इनमें संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), बहरीन, मोरक्को और सूडान शामिल हैं। अमेरिकी परमाणु क्षेत्र में नए विकास पर अपने संबोधन में ट्रंप ने प्रस्तावित ऊर्जा साझेदारी के केंद्र में अब्राहम समझौते को रखा। उन्होंने कहा कि इस्राइल के साथ क्षेत्रीय संबंध सामान्य करने वाले इस समझौते में शामिल होना 'पश्चिम एशिया के भविष्य के लिए बहुत अहम' है। ट्रंप ने कहा, इसे पूरा करने के लिए उन्हें अब्राहम समझौते का सदस्य बनना होगा। अब समय आ गया है कि वे ऐसा करें। उन्होंने कहा, वे और अन्य देश ऐसा नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें ईरान से समस्या थी। अब वह समस्या नहीं है। अब वहां कोई बड़ी ताकत नहीं है। वे पश्चिम एशिया के दबंग थे। अब वे इतने बड़े दबंग नहीं रहेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, किसी न किसी समय वे इसमें शामिल होंगे।

ट्रंप ने एक दिन पहले ट्रुथ सोशल पर कहा था कि ऊर्जा समझौता केवल गैर-सैन्य परमाणु इस्तेमाल तक सीमित रहेगा और सऊदी अरब में घरेलू स्तर पर यूरेनियम संवर्धन की अनुमति नहीं होगी। ट्रंप ने गुरुवार को लिखा था, नागरिक परमाणु समझौते को मंजूरी दी जाएगी। लेकिन यह पूरी तरह से सऊदी अरब के अब्राहम समझौते में शामिल होने पर निर्भर है। अमेरिका नागरिक (बिना संवर्धित) परमाणु सुविधाओं का विरोध नहीं करता।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया में मिला बड़ा शैक्षणिक सम्मान

रोमानिया, एजेंसी। रोमानिया की राजकीय यात्रा पर पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शुक्रवार को बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने अपनी सर्वोच्च शैक्षणिक उपाधि 'डॉक्टर होनोरिस कॉसा' से सम्मानित किया। यह सम्मान शिक्षा, सार्वजनिक सेवा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग में असाधारण योगदान देने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों को दिया जाता है। सम्मान स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने इसे अपने लिए गर्व का क्षण बताया और कहा कि वह इसे विनम्रता के साथ भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत-रोमानिया की स्थायी मित्रता के सम्मान के रूप में स्वीकार करती हैं।

राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा उनके जीवन की सबसे परिवर्तनकारी शक्ति रही है। उन्होंने बताया कि उनका जन्म एक छोटे से गांव में सीमित संसाधनों वाले परिवार में हुआ था और वह अपने गांव की पहली लड़की थीं, जिसने कॉलेज में प्रवेश लिया। उन्होंने कहा कि इस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि शिक्षा सबसे बड़ा समान अवसर देने वाला माध्यम है। शिक्षा यह नहीं देखती कि कोई कहां पैदा हुआ, बल्कि यह देखती है कि वह कितनी दूर तक आगे बढ़ने की इच्छा रखता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में कुछ समय तक शिक्षक के रूप में काम करने का अवसर मिला, जहां उन्होंने देखा कि एक साधारण कक्षा भी किसी परिवार और धीरे-धीरे पूरे समाज का भविष्य बदल सकती है।

राष्ट्रपति ने शिक्षा को समाज की सबसे बड़ी ताकत क्यों बतायाः राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में उनके पूरे सफर के दौरान यह विश्वास बना रहा कि शिक्षा केवल किसी व्यक्ति की तरक्की का साधन नहीं है, बल्कि न्यायपूर्ण और समावेशी समाज की सबसे मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल तकनीक और तेज वैज्ञानिक प्रगति के दौर से गुजर रही है, तब विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि ज्ञान के साथ विवेक, नैतिकता और करुणा का होना भी उतना ही आवश्यक है।

ट्रंप ने ईयू को दी टैरिफ की धमकी, चीन-कनाडा और रूस-यूक्रेन को लेकर क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने यूरोपीय संघ पर अमेरिकी टेक कंपनियों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ लगातार अमेरिका की बड़ी कंपनियों को निशाना बना रहा है। ट्रंप के मुताबिक, एप्पल, मेटा, अमेजन और अब गूगल पर लगाए गए भारी जुर्माने इसका उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब इस मामले को चुपचाप नहीं देखेगा और इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय संघ ने पहले बिना किसी वजह के एप्पल पर 15 अरब डॉलर, मेटा पर 3 अरब डॉलर, अमेजन पर 2.5 अरब डॉलर और कई अन्य अमेरिकी कंपनियों पर जुर्माना लगाया। उन्होंने दावा किया कि अब गूगल पर भी एक अरब डॉलर का नया जुर्माना लगाया गया है, जिससे गूगल पर कुल जुर्माने की राशि 18 अरब डॉलर से अधिक हो गई है। ट्रंप ने कहा कि यह गैरकानूनी और अत्यधिक भेदभावपूर्ण तरीका है।

ट्रंप ने यूरोपीय संघ पर क्या आरोप लगाएः ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल के पहले वर्ष में ऊंचे स्तर पर हुई थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के दौरान यह स्थिति जारी नहीं रहने दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूरोप के लिए कोई 'पिगी बैंक' नहीं है और वह अमेरिकी कंपनियों तथा अमेरिकी करदाताओं के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं करेगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूरोपीय संघ द्वारा अमेरिकी कंपनियों को 'लूटने' की कथित प्रथा की 301 जांच तुरंत शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि यह संदेश आधिकारिक चेतावनी के रूप में देखा जाना चाहिए। उनके अनुसार, अमेरिकी कंपनियों और करदाताओं को नुकसान पहुंचाने वाली इस नीति की पूरी जांच की जाएगी।

यूरोपीय संघ के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई की बात कहीः ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय संघ को इस कथित गैरकानूनी और अनैतिक व्यवहार की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि लगाए गए दंड पूरी तरह पलट दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ पर जल्द से जल्द बड़ा टैरिफ लगाने की भी उम्मीद है। ट्रंप ने अपने बयान के अंत में कहा कि आगे की कार्रवाई के लिए इंतजार कीजिए।

चीन के राष्ट्रपति पर क्या बोले ट्रंपः अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में हालिया मुलाकात के दौरान उन्हें भरोसा दिया।

राजनीतिक दबाव में है नेपाल का सुप्रीम कोर्ट, बालेंद्र सरकार पर उठे सवाल; अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने लगाए आरोप

काठमांडू, एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने नेपाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की नियुक्तियों और उसकी संरचना में राजनीतिक हस्तक्षेप से बाज आने के लिए आगाह करते हुए इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स (आईसीजे) ने शुक्रवार को जारी संयुक्त बयान में कहा कि नेपाल सरकार की ओर से हाल ही में उठाए गए कदम देश की न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरे में डालते हैं। क्या जजों पर इस्तीफे और महाभियोग का दबाव बनाया जा रहा है बयान में कहा गया कि मौजूदा जजों के जबरन इस्तीफे या महाभियोग के जरिए सुप्रीम कोर्ट की संरचना को बदलने के लिए राजनीतिक दबाव डाले जाने की खबरें सामने आई हैं। मई 2026 में नेपाल के संविधान और कानून के सिद्धांतों के तहत आवश्यक संसदीय कानून के बजाय एक कार्यकारी अध्यादेश के माध्यम से संवैधानिक परिषद अधिनियम में संशोधन करने को इन संगठनों ने अनुचित करार दिया। मानवाधिकार समूहों ने प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के नेतृत्व वाली सरकार से जजों पर दबाव बनाना बंद करने और न्यायिक स्वतंत्रता से खिलवाड़ न करने की चेतावनी दी। क्या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता की परंपरा तोड़ी गई मानवाधिकार समूहों का मानना है कि तीन वरिष्ठ जजों की मौजूदगी के बावजूद मनोज कुमार शर्मा को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।

NEET पेपर लीक के विरोध में नईगढ़ी में कांग्रेस का कैंडल मार्च, छात्रों के समर्थन में उठी न्याय की मांग

मीडिया ऑडीटर, मऊगंज (निप्र)। मऊगंज जिले के नईगढ़ी में शनिवार शाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हृश्वश्वञ्ज पेपर लीक प्रकरण और दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने दिवंगत विद्यार्थियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता तथा छात्रों को न्याय दिलाने की मांग उठाई कैंडल मार्च का नेतृत्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश पटेल ने किया। यह मार्च नईगढ़ी ब्लॉक चौराहे से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होते हुए सब्जी मंडी तक पहुंचा। प्रतिभागियों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर शांतिपूर्ण ढंग से मार्च निकाला और विभिन्न स्थानों पर रुककर छात्रों के प्रति संवेदना व्यक्त की इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पेपर लीक जैसे मामलों से लाखों विद्यार्थियों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उनका कहना था कि प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और यदि परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठते हैं तो उससे छात्रों का विश्वास कमजोर होता है मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने उन विद्यार्थियों को श्रद्धांजलि दी, जिनकी मौत को कांग्रेस नेताओं ने परीक्षा विवाद से जोड़ते हुए याद किया। साथ ही उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित लाठीचार्ज किया गया, जिसका वे विरोध करते हैं। उनके अनुसार, लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है और ऐसे प्रदर्शनों पर बल प्रयोग उचित नहीं माना जा सकता। ब्लॉक अध्यक्ष अखिलेश पटेल ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्र शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की आवाज उठा रहे थे उन्होंने कहा कि छात्रों की मांगों को सुनने के बजाय पुलिस कार्रवाई की गई, जिससे कई छात्र घायल हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छात्रों के अधिकारों की लड़ाई में उनके साथ खड़ी है और लोकतांत्रिक तरीके से उनके समर्थन में आवाज उठाती रहेगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की कि प्रतियोगी परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए, परीक्षा प्रक्रिया में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं तथा भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की कैंडल मार्च के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी सतर्क रही। पूरे कार्यक्रम के दौरान मार्च शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली इस कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष राम सजीवन सोनी, शिवेंद्र सिंह 'शिबू', रोशन खान, शेषमणि पटेल, मुन्नू खान, शैलेंद्र पटेल, शुभम सोनी, सच्चेलाल पटेल, हरशलाल गुप्ता, रमेश पटेल, विश्वनाथ साकेत, उमेश पटेल, लक्ष्मण पटेल, संजय सोनी, संजीत कुशवाहा, श्रीनिवास कुशवाहा, कमलेश कोल, रामलखन पटेल, खुर्शीद खान, अभिजीत श्रीवास्तव, अभिषेक कुशवाहा, शिवेंद्र सोनी, बृजेंद्र सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

राहुल गांधी की गिरफ्तारी व छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज कांग्रेस का सत्याग्रह, निजी कार्यक्रम से संगठन ने किया किनारा

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। जिला शहर कांग्रेस कमेटी, रीवा ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे 'रीवा शहर कांग्रेस संवाद एवं स्नेह मिलन समारोह' को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह कांग्रेस पार्टी का अधिकृत कार्यक्रम नहीं है शहर कांग्रेस अध्यक्ष अशोक पटेल 'झब्बू' ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कार्यकर्ताओं और आमजन से अपील की है कि वे केवल पार्टी द्वारा जारी आधिकारिक कार्यक्रमों पर ही विश्वास करें अशोक पटेल ने बताया कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर 25 जुलाई 2026 को चिरहुला ब्लॉक स्थित सिंधु भवन में आयोजित होने वाले 'रीवा शहर कांग्रेस संवाद एवं स्नेह मिलन समारोह' का पोस्टर प्रसारित किया जा रहा है उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्यक्रम की न तो जिला शहर कांग्रेस कमेटी को कोई सूचना दी गई है और न ही इसकी अनुमति या स्वीकृति संगठन की ओर से प्रदान की गई है यह कार्यक्रम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अथवा जिला कांग्रेस संगठन द्वारा अधिकृत नहीं है उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्देशानुसार 25 जुलाई को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी तथा दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में सत्याग्रह एवं कैंडल मार्च का आधिकारिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के आह्वान पर आयोजित हो रहा हैशहर कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील की कि वे केवल अधिकृत सत्याग्रह एवं कैंडल मार्च में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित निजी कार्यक्रमों को कांग्रेस का आधिकारिक आयोजन मानकर भ्रमित न हों उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन की ओर से जारी कार्यक्रमों की जानकारी जिला, ब्लॉक एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अधिकृत माध्यमों से ही प्राप्त करें, ताकि किसी प्रकार की भ्रांति की स्थिति उत्पन्न न हो जिला कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि पार्टी अनुशासन और संगठनात्मक व्यवस्था को बनाए रखना सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है।

केंद्रीय विद्यालय सीधी में विद्यार्थियों के समग्र विकास पर जोर, नीट-जेईई तैयारी के लिए बनेगा विशेष अकादमिक समूह

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। केंद्रीय विद्यालय सीधी के विद्यार्थियों को अब शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं, करियर निर्माण और व्यक्तित्व विकास के लिए बेहतर मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में कलेक्टर एवं समिति अध्यक्ष विकास मिश्रा ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और विद्यालय की सुविधाओं के विस्तार को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। शनिवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर विकास मिश्रा ने की बैठक में विद्यार्थियों के शैक्षणिक, बौद्धिक एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही विद्यालय की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन और व्यावहारिक समझ विकसित करने के लिए प्रत्येक माह विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों के व्याख्यान एवं सेमिनार आयोजित किए जाएंगे इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को रिसोर्स पर्सन के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। इन कार्यक्रमों में वित्तीय साक्षरता, साइबर अपराध से सुरक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य, करियर काउंसलिंग, न्यायिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था तथा वन एवं पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी कलेक्टर विकास मिश्रा ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विशेष शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी नीट और जेईई जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बेहतर मार्गदर्शन मिलना चाहिए। इसके लिए एलन करियर इंस्टीट्यूट और केंद्रीय विद्यालय सीधी के विषय विशेषज्ञ शिक्षकों का संयुक्त अकादमिक समूह गठित किया जाएगा इस समूह के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता मिलेगी साथ ही एलन करियर इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार अध्ययन सामग्री भी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी बैठक में विद्यार्थियों को प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी देने के लिए कलेक्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, बैंक, न्यायालय सहित अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों का शैक्षणिक भ्रमण कराने का सुझाव भी दिया गया इससे विद्यार्थी सरकारी व्यवस्थाओं और कार्यप्रणाली को नजदीक से समझ सकेंगे विद्यालय की सुविधाओं के विस्तार को लेकर भी कई निर्णय लिए गए।

सरकारी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को मिलेगा एलन का साथ, जिला प्रशासन शुरू करेगा प्रतियोगी परीक्षा मार्गदर्शन अभियान

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। सीधी जिले के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत मेधावी विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब अधिक व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण होगी जिला प्रशासन ने सरकारी स्कूलों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने की अभिनव पहल शुरू की है इस अभियान के तहत विद्यार्थियों को विशेषज्ञ मार्गदर्शन, उच्च गुणवत्ता का अध्ययन सामग्री, शिक्षकों का प्रशिक्षण और नियमित शैक्षणिक मॉनिटरिंग उपलब्ध कराई जाएगी कलेक्टर विकास मिश्रा ने बताया कि जिले में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता केवल उन्हें उचित दिशा और अवसर उपलब्ध कराने की है। इसी उद्देश्य से जिले के सभी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत मेधावी विद्यार्थियों का चिन्हांकन कर उन्हें आईआईटी-जेईई, नीट तथा अन्य राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष शैक्षणिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पहल केवल कोचिंग तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि विद्यार्थियों के समग्र शैक्षणिक विकास का मजबूत आधार बनेगी इस महत्वाकांक्षी अभियान में एलन करियर इंस्टीट्यूट, इंदौर जिला प्रशासन का अकादमिक सहयोगी बना है। शनिवार को जिला मुख्यालय में आयोजित बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा, कार्यप्रणाली और क्रियान्वयन की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। एलन करियर इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधि सचिन दुबे ने बताया कि सेंटर हेड कमल शर्मा के नेतृत्व में संस्थान की टीम विद्यार्थियों और शिक्षकों को हर संभव शैक्षणिक सहयोग प्रदान करेगी योजना के तहत विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप उच्च गुणवत्ता का स्टडी मैटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही विषय विशेषज्ञों द्वारा नियमित मार्गदर्शन, परीक्षा रणनीति, करियर काउंसलिंग और शैक्षणिक सहायता भी दी जाएगी। विद्यालयों के शिक्षकों के लिए ओरिएंटेशन एवं क्षमता विकास प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे, जिससे वे आधुनिक शिक्षण पद्धतियों और प्रतियोगी परीक्षाओं के बदलते स्वरूप के अनुरूप विद्यार्थियों का बेहतर मार्गदर्शन कर सकें कार्यक्रम के प्रभावी संचालन के लिए जिले के प्रत्येक विकासखंड में एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के शासकीय विद्यालयों में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चिन्हांकन, कार्यक्रम का समन्वय, नियमित मॉनिटरिंग और प्रगति की समीक्षा सुनिश्चित करेंगे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जिले का प्रत्येक पात्र विद्यार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सके।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम में लापरवाही पर कार्रवाई, दो पंचायत सचिवों पर 1-1 हजार का अर्थदंड

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने वाले दो पंचायत सचिवों पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) तथा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी विकास मिश्रा ने समय पर आवेदनों का निराकरण नहीं करने और पूर्व में जारी कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देने पर दोनों पंचायत सचिवों पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है जारी आदेश के अनुसार योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित अधिसूचित सेवाओं के विभागीय पोर्टल की समीक्षा के दौरान कई आवेदन निर्धारित समय-सीमा से अधिक अवधि तक लंबित पाए गए। यह स्थिति लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन मानी गई, क्योंकि अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को तय समय में शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराना है प्रशासन ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को पहले ही कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। इसके बावजूद न तो समय पर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत किया गया और न ही लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया। परिणामस्वरूप आवेदकों को समय पर सेवाओं का लाभ नहीं मिल सका, जिससे प्रशासन ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए दंडात्मक कार्रवाई की।

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 6(2) एवं 7(1)(क) के तहत ग्राम पंचायत पिपरहा, जनपद पंचायत सिहावल के पंचायत सचिव अविनाश चतुर्वेदी तथा ग्राम पंचायत हनुमानगढ़, जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के पंचायत सचिव लालमणि सिंह पर 1-1 हजार का अर्थदंड लगाया गया है प्रशासन का कहना है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत सभी अधिसूचित सेवाओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं करने और नागरिकों को अनावश्यक परेशानी में डालने वाले अधिकारियों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी कलेक्टर विकास मिश्रा ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए तथा भविष्य में ऐसी लापरवाही की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम नागरिकों को समय पर शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।

शहडोल को मिली नई कलेक्टर, मिशा सिंह संभालेंगी जिले की कमान; डॉ. केदार सिंह बने PWD के अपर सचिव

मीडिया ऑडीटर,शहडोल (निप्र)। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण फेरबदल करते हुए शहडोल जिले को नई कलेक्टर दी है। वर्ष 2016 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी मिशा सिंह को शहडोल का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। वहीं, वर्तमान कलेक्टर डॉ. केदार सिंह का तबादला कर उन्हें भोपाल स्थित लोक निर्माण विभाग में अपर सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मिशा सिंह इससे पहले रतलाम जिले में कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही थीं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, जनसुनवाई की प्रभावी व्यवस्था और राजस्व मामलों के त्वरित निराकरण को प्राथमिकता दी। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति जानने के लिए वे नियमित रूप से मैदानी निरीक्षण करती रही हैं उनकी कार्यशैली को संवेदनशील और परिणामोन्मुखी माना जाता है। रतलाम से पहले मिशा सिंह जबलपुर में अपर कलेक्टर के पद पर भी कार्य कर चुकी हैं। वहां उन्होंने भूमि संबंधी प्रकरणों, कानून-व्यवस्था, निर्वाचन कार्यों और प्रशासनिक समन्वय जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया प्रशासनिक अनुभव और प्रभावी कार्यशैली को देखते हुए राज्य सरकार ने अब उन्हें शहडोल जिले की जिम्मेदारी सौंपी है।

दूसरी ओर, शहडोल के कलेक्टर रहे डॉ. केदार सिंह का कार्यकाल भी उपलब्धियों से भरा रहा। लगभग दो वर्षों तक जिले का नेतृत्व करते हुए उन्होंने जल संरक्षण अभियानों को गति दी, अवैध उत्खनन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा नियमित जनसुनवाई के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान दिया गया सरकार के नए आदेश के अनुसार डॉ. केदार सिंह अब भोपाल में लोक निर्माण विभाग में अपर सचिव के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे वहीं, मिशा सिंह शीघ्र ही शहडोल पहुंचकर कलेक्टर पद का कार्यभार ग्रहण करेंगी। प्रशासनिक हलकों में इस बदलाव को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

रीवा में कांग्रेस का सत्याग्रह, NEET पेपर लीक और राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। जिला कांग्रेस कमेटी रीवा ग्रामीण एवं शहर के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को NEET एवं सीबीएसई परीक्षा पेपर लीक प्रकरण, छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई तथा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किया गया। सिरमौर चौराहा स्थित पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा के समक्ष आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए छात्रों के हितों की रक्षा की मांग उठाई कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष इंजी. राजेन्द्र शर्मा ने की। इस दौरान सेमरिया विधायक अभय मिश्रा, जिला संगठन प्रभारी रामलखन पटेल, पूर्व राज्यसभा सदस्य राजमणि पटेल तथा रीवा महापौर अजय मिश्रा बाबा विशेष रूप से उपस्थित रहे सभा को संबोधित करते हुए इंजी. राजेन्द्र शर्मा ने कहा कि छात्रों के आंदोलन और राहुल गांधी के प्रयासों से जुड़े मुद्दों ने देशभर में शिक्षा व्यवस्था पर बहस को तेज किया है उन्होंने इसे लोकतंत्र में युवाओं की जागरूकता का प्रतीक बताया पूर्व राज्यसभा सदस्य राजमणि पटेल ने कहा कि देश का युवा अब अपने अधिकारों के प्रति सजग हो चुका है और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता चाहता है सेमरिया विधायक अभय मिश्रा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया वहीं महापौर अजय मिश्रा बाबा ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि शिक्षा से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय होनी चाहिए। जिला संगठन प्रभारी एवं पूर्व विधायक रामलखन पटेल ने छात्रों के समर्थन में राहुल गांधी द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए कहा कि अन्याय के विरुद्ध कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा।

कलेक्ट्रेट गेट पर बिना अनुमति प्रदर्शन पड़ा भारी, 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज

सरकारी अधिकारियों पर अभद्र टिप्पणी और सार्वजनिक स्थल पर अमर्यादित प्रदर्शन का आरोप, वीडियो फुटेज के आधार पर जांच जारी

मीडिया ऑडीटर, मऊगंज (निप्र)। मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय के मुख्य द्वार पर बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन करने, सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग करने और सार्वजनिक स्थल पर अमर्यादित आचरण करने के आरोप में पुलिस ने 10 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है यह कार्रवाई कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर की गई है पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और घटना से जुड़े वीडियो फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों का परीक्षण किया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शशिकांत सरयाम के अनुसार, 23 जुलाई को नईगढ़ी तहसील के रामपुर निवासी कुंज बिहारी तिवारी अपने 8 से 10 साथियों के साथ मऊगंज कलेक्ट्रेट पहुंचे थे आरोप है कि समूह ने सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लिए बिना कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया पुलिस के अनुसार प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने शासकीय अधिकारियों के संबंध में कथित रूप से अभद्र टिप्पणियां कीं आरोप यह भी है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक स्थल पर कपड़े उतारकर प्रदर्शन किया गया, जिससे वहां मौजूद लोगों में असहज स्थिति बनी और लोक व्यवस्था प्रभावित हुई प्रशासन ने इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

पुलिस ने कुंज बिहारी तिवारी एवं उनके साथियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296(ए), 132, 351(2), 191(1) और 223 के तहत एफआईआर दर्ज की है पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया है तथा जांच के दौरान उपलब्ध होने वाले तथ्यों के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी जांच अधिकारी घटना के दौरान बनाए गए वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप, सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान जुटा रहे हैं पुलिस का कहना है कि यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि घटना से जुड़े सभी डिजिटल और भौतिक साक्ष्यों का बारीकी से परीक्षण किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग भी खंगाली जा रही है साथ ही घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं ताकि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की जा सके पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद यदि किसी अतिरिक्त अपराध या अन्य व्यक्तियों की भूमिका सामने आती है, तो उसके अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले के बाद मऊगंज पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज कराने का अधिकार देता है हालांकि, किसी भी प्रकार का धरना-प्रदर्शन कानून के निर्धारित प्रावधानों और प्रशासनिक अनुमति के अनुरूप होना चाहिए।

पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक शालीनता, कानून-व्यवस्था और सरकारी कार्यों में बाधा न पहुंचे, इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए प्रशासन ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे अपनी मांगों या शिकायतों के संबंध में ज्ञापन, धरना या प्रदर्शन करते समय निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करें पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह मामला अभी जांच के चरण में है दर्ज एफआईआर आरोपों के आधार पर की गई है और अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही सामने आएगा वीडियो फुटेज, दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी व्यक्ति को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है लेकिन वह कानून के दायरे और सार्वजनिक मर्यादा के अनुरूप ही होना चाहिए इसी उद्देश्य से इस मामले में विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है।

उद्योगों के लिए पारदर्शी व्यवस्था

संपादकीय

जब कोई राज्य उद्योगों के लिए भरोसेमंद और पारदर्शी व्यवस्था को कानून का हिस्सा बना देता है, तो यह केवल सरकारी प्रक्रियाओं में सुधार नहीं होता, बल्कि सरकार और उद्योगों के बीच भरोसे के रिश्ते को भी मजबूत करता है। 16 जुलाई को छत्तीसगढ़ विधानसभा ने छत्तीसगढ़ ईज आफ डूइंग बिजनेस अधिनियम, 2026 पारित किया। इसे कानूनी जिम्मेदारी बनाने का फैसला भी लिया गया है। निवेशकों, उद्यमियों और उद्योगों के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भरोसा तभी बनता है, जब नियम स्पष्ट हों, काम तय समय-सीमा में हो और जवाबदेही भी तय हो। यह अधिनियम एक सरल सोच पर आधारित है कि नियम के अनुसार काम करने वाले उद्योगों को अनावश्यक मंजूरियों, लाइसेंस के नवीनीकरण और एक ही काम के लिए बार-बार अलग-अलग अनुमतियां लेने की प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहिए। निवेशक अवसरों को महत्व देते हैं, लेकिन उनके लिए यह भरोसा भी उतना ही जरूरी है कि सरकारी प्रक्रियाएं स्पष्ट, तय नियमों के अनुसार और समय पर पूरी हों। उद्यमी चाहते हैं कि उनके काम में तेजी आए, लेकिन वे ऐसी शासन व्यवस्था भी चाहते हैं, जो स्पष्ट, पारदर्शी और समय पर निर्णय लेने वाली हो। हमारा यह सुधार उन्हें ये दोनों सुविधाएं देता है, अनावश्यक प्रक्रियाओं में कमी और यह भरोसा कि राज्य तय नियम और निर्धारित समय सीमा के अनुसार काम करेगा। हमने यह कानून केवल रैंकिंग में सुधार के लिए नहीं बनाया है, बल्कि वास्तविक बदलाव और बेहतर परिणाम लाने के उद्देश्य से बनाया है। छत्तीसगढ़ ईज आफ डूइंग बिजनेस अधिनियम, 2026 इस व्यवस्था को बदलकर जोखिम के आधार पर काम करने वाली प्रणाली लागू करता है। कम जोखिम वाले उद्योग बिना भौतिक निरीक्षण के स्व-प्रमाणन के आधार पर आगे बढ़ सकेंगे। मध्यम जोखिम वाले उद्योग सूचीबद्ध तृतीय-पक्ष विशेषज्ञों से प्रमाणन प्राप्त कर सकेंगे। वहीं, उच्च जोखिम वाले उद्योगों की गहन तकनीकी जांच पहले की तरह जारी रहेगी, क्योंकि भरोसे पर आधारित व्यवस्था का मतलब जोखिम की अनदेखी करना नहीं है। लेकिन ऐसे मामलों में भी जांच तय समय-सीमा के भीतर पूरी करनी होगी। यदि छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा में प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाता, तो स्वीकृति स्वतः प्राप्त मानी जाएगी। वहीं, तीन दिन से अधिक की किसी भी देरी का मामला सीधे कार्यपालक परिषद को भेजा जाएगा। इस व्यवस्था के पीछे सोच स्पष्ट है। जहां जोखिम ज्यादा है, वहां सरकारी निगरानी भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए और जहां जोखिम कम है, वहां प्रक्रिया भी उतनी ही सरल होनी चाहिए। इसका मतलब नियमों को खत्म करना नहीं, बल्कि उन्हें और बेहतर एवं प्रभावी बनाना है। यदि किसी उद्योग का जोखिम कम है, तो उसे अनावश्यक मंजूरियों और लंबी प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना चाहिए। वहीं, जिन उद्योगों में तकनीकी जांच जरूरी है, वहां सरकार पूरी जांच करेगी, लेकिन यह भी सुनिश्चित करेगी कि यह काम तय समय-सीमा के भीतर पूरा हो। इसलिए यह अधिनियम जहां जरूरत से ज्यादा औपचारिकताएं हैं, उन्हें कम करता है और जहां निगरानी जरूरी है, वहां पारदर्शिता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। इस पहल का सबसे बड़ा फायदा राज्य के 15 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को मिलेगा, जो हमारी अर्थव्यवस्था की असली ताकत हैं।

स्वस्थ भारत की दिशा में शुभ संकेत है प्राकृतिक खेती का बढ़ना !

डॉ. मयंक चतुर्वेदी

भारत की कृषि क्रांति आज उत्पादन सफलता की वो कहानी कह रही है, जिससे कि विश्व के 150 से अधिक देश लाभान्वित हो रहे हैं, ऐसे में अब प्रश्न यह है कि जो अन्न हमारी थाली तक पहुंच रहा है, वह कितना सुरक्षित है, कितना पौष्टिक है और आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य को कितना सशक्त बना सकेगा। वस्तुतः पिछले कई दशकों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग ने कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि तो की, किंतु इसके साथ ही मिट्टी की उर्वरता, जल स्रोतों की गुणवत्ता, जैव विविधता और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रश्न भी खड़े कर दिए। कैंसर, हार्मोनल असंतुलन, मधुमेह, एलर्जी और अनेक गैर-संचारी रोगों के बढ़ते मामलों के बीच अब पूरी दुनिया टिकाऊ और प्राकृतिक कृषि की ओर लौट रही है, जिसमें कि भारत इसी परिवर्तन का नेतृत्व करता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले बारह वर्षों में प्राकृतिक खेती को स्वस्थ किसान, स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ पर्यावरण और स्वस्थ भारत के राष्ट्रीय अभियान के रूप में स्थापित करने का प्रयास हुआ है। यही कारण है कि आज प्राकृतिक खेती का बढ़ता दायरा देश के भविष्य की नई दिशा का संकेत बन गया है।

बारह वर्षों में बदली कृषि विकास की सोच

वर्ष 2014 के बाद केंद्र सरकार ने कृषि नीति को उत्पादन-केंद्रित दृष्टिकोण से बाहर निकालना आरंभ कर दिया था। उद्देश्य यह रखा गया कि कृषि स्वास्थ्य लाभ के वैज्ञानिक नजरिए से हो। कहना होगा कि इसका पहला बड़ा कदम वर्ष 2015 में शुरू की गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना थी। पहली बार किसानों को उनकी भूमि की वास्तविक स्थिति का वैज्ञानिक विश्लेषण उपलब्ध कराया गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि खेत को वास्तव में किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है। तब परिणाम में दिखा कि इससे उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग पर नियंत्रण संभव हुआ और संतुलित पोषण की संस्कृति विकसित होने लगी। आज इसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। केंद्र सरकार के अनुसार 25.89 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जोकि करोड़ों किसानों तक वैज्ञानिक कृषि ज्ञान पहुंचाने का सबसे बड़ा अभियान बन चुका है। इससे संतुलित उर्वरक उपयोग से जहां खेती की लागत कम हुई है, वहीं मिट्टी की जैविक गुणवत्ता में सुधार और दीर्घकालिक उत्पादकता बढ़ाने का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है।

प्राकृतिक खेती अब राष्ट्रीय अभियान है

प्राकृतिक खेती को प्रारंभिक प्रयोगों से निकालकर व्यापक जनभागीदारी वाले कार्यक्रम का स्वरूप देने के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को गति प्रदान की है। ताजा सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो दिखाई यही देता है कि यह मिशन अब 18,786 क्लस्टरों तक पहुंच चुका है, जो 8.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हैं। देश के अनेक राज्यों में लाखों किसान प्राकृतिक खेती, जैविक खेती अथवा कम-रासायनिक कृषि पद्धतियों को अपना रहे हैं। विशेष रूप से आंध्र प्रदेश की सामुदायिक प्राकृतिक खेती, हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक कृषि खुशहाल किसान योजना, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न मॉडल यह सिद्ध कर रहे हैं कि यदि नीति सही दिशा में हो, प्रशिक्षण और बाजार का उचित सहयोग मिलना आरंभ हो जाए तो किसान स्वेच्छा से रसायन आधारित खेती से बाहर निकलने को तैयार हैं, इसीलिए ही आज प्राकृतिक खेती राष्ट्रीय कृषि विमर्श का केंद्रीय विषय बन चुकी है।

मिट्टी की सेहत सुधरेगी, तभी भोजन बनेगा अमृत

भारतीय परंपरा में धरती को माता कहा गया है। यदि माता ही बीमार होगी तो उससे प्राप्त अन्न भी पूर्णतः पोषक नहीं हो सकता। यही वैज्ञानिक सत्य आज आधुनिक कृषि विज्ञान भी स्वीकार कर रहा है। मिट्टी में जैविक कार्बन, सूक्ष्म पोषक तत्व और लाभकारी जीवाणुओं की पर्याप्त मात्रा ही गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की आधारशिला है। इसी उद्देश्य से सरकार ने एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसियों (आत्मा) और कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के माध्यम से अब तक करीब 7.17 लाख प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

इन कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक खेती,

जंतर -मंतर से शिक्षा

पछले कुछ दिनों से राजनीति के हलकों में शिक्षा का विषय अनायास ही चर्चा में चुका है । सबकी जुबान वर्तमान शिक्षा-तंत्र को सुधारने की रट लगा रही है । लगता है शिक्षा की समस्याओं और उनके समाधान को लेकर देश के कर्णधारों में सद्भावना जगी है । इसमें सभी शिक्षा-प्रेमियों को आशा की किरण दिख रही है । निश्चय ही एक अच्छी बात है कि शिक्षा की समस्या की तरफ़ राजनीतिक तंत्र का ध्यान आकृष्ट हुआ है । विपक्ष के नेता आज युवा छात्र समुदाय के हित की चिंता करने में भरसक जी जान से जुटे हुए हैं । संसद से सड़क तक आक्रामक रुख़ के साथ ज्यादातर विपक्षी दल अपनी राजनैतिक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आज समर्पित दिख रहा है । आईएनडीआईए के बिखरते कुनबे के सदस्य आंदोलन के ज़रिए अपनी माँग पर खड़े दिख रहे हैं । उनकी माँग है कि वर्तमान शिक्षा मंत्री इस्तीफ़ा दें । तर्क है कि उनकी मुखियागिरी में हुई नीट की परीक्षा में पेपर लीक हुआ और लाखों युवा परीक्षार्थियों और उनके परिजनों को तरह-तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा इसलिए जिम्मेदारी लेते हुए उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए या सरकार को उनसे इस्तीफ़ा के लेना चाहिए ।

गिरीश्वर मिश्र

अिभी-अभी जन्मी काक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) और सोनम वांगचुक, जो लद्दाख के समाजकर्मी हैं और अध्यापक की पृष्ठभूमि वाले हैं, आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। वांगचुक ने 26 दिनों से चल रहे अनशन को तोड़ दिया है। साठ साल के हो रहे वांगचुक अपने अस्पताल से दिए गए वीडियो-संदेश में सबसे शांति और अहिंसा के साथ लड़ाई की बात करते हैं। विपक्षी राजनीति इस अवसर पर अपना विपक्षी धर्म निभाने में जुट गई है। वह संसद के मानसून सत्र को चलने नहीं देने के लिए आमादा है। साथ ही सड़क पर और प्रधानमंत्री आवास पर मार्च और धरना-प्रदर्शन में जुटा रहा है। देशव्यापी मार्च की योजना है। ये नेता शिक्षा में सुधार ले आने की बात भी कहते हैं पर मंत्री के इस्तीफे से ज़्यादा सुधार की कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। इन नेताओं को शिक्षा से कभी ख़ास लेना-देना नहीं रहा है, इसलिए वे राजनीतिक अवसर के रूप में ले रहे हैं। इसके बावजूद यदि वे शिक्षा का नाम ले रहे हैं तो यह शिक्षा प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह बेहद जरूरी है कि शिक्षा-व्यवस्था पर समग्रता में विचार किया जाय। जंतर-मंतर शिक्षा जैसे गहन और गंभीर विषय पर बहुत सहायक न होगा। इस पर गंभीर चर्चा की ज़रूरत है और गलतियों को सुधार कर नई राह ढूँढने की आवश्यकता है।

पेपर लीक होना कोई नई बात नहीं है। यह अपराध है जिसमें लिप्त लोगों को दंडित किया ही जाना चाहिए। अब तक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पिछले दस-बारह सालों में कुल मिला कर लगभग डेढ़ सौ बार परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनायें जाहिरी तौर पर दर्ज हो चुकी हैं। सरकार ने इस बार के मामले में गिरफ़्तारी की है और इससे जुड़े लोगों को जेल भेजकर कार्रवाई की जा रही है। सरकार सख्ती से निपटने के लिए कानून भी बना रही है। फ़ास्ट ट्रैक अदालत गठित कर मामलों पर त्वरित कार्रवाई की तैयारी हो रही है। यह अलग बात है कि ऐसे मामलों में कभी किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाती है। गंगा पर पुल गिर जाता है और यह तय नहीं हो पाता कि कौन जिम्मेदार है। गंगा जी ही शायद निगल गईं। उन्हें ही कुछ संदेश देना हो। यानी पेपर लीक बहुत-सी परीक्षाओं में जगह-जगह पर होता आ रहा है और लोगों को इसकी आदत-सी पड़ गई है। लेकिन साल्वर गैंग सक्रिय है और बोर्ड परीक्षा में नकल जिस पैमाने पर होती है वह क़ानून व्यवस्था का प्रश्न बन जाता है और कभी-कभी धारा 144 लगाने की नौबत आ जाती है। यह भी गौर करने की बात है कि इस साल हुई नीट की पहली परीक्षा जिसमें लीक हुआ था बीस लाख से अधिक छात्र बैठे थे। पेपर लीक होने से इन्हें बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ी थी। सरकार ने चाक-चौबंद होकर दुबारा परीक्षा कराई जिसमें उन्नीस लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए और लीक जैसी दुर्घटना नहीं हुई । अब नीट की पुनर्परीक्षा का परिणाम आ चुका है जिसमें ग्यारह लाख से कुछ ज़्यादे की संख्या में छात्र प्रवेश-योग्य पाये गए हैं। इनमें 58 प्रतिशत से अधिक छात्रायें हैं। वर्तमान में देशभर के 823 मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस में प्रवेश पाने के लिए कुल 1,36,939 सीटें ही उपलब्ध हैं। इसका आशय है प्रवेशार्थियों का मनोबल ऊंचा था और उन्होंने इस मुश्किल का डटकर मुकाबला किया। पर यह घटनाक्रम एक विकट संकट की ओर भी संकेत करता है। ये आंकड़े हमारी शिक्षा-प्रणाली की कमज़ोरियों और समाज की मानसिकता को लेकर बहुत कुछ कह रहे हैं। नीट में प्रवेश की मंशा पर भी सोचना होगा और जीविका के लिए उपलब्ध अवसरों पर भी गौर करना होगा। कम सीटों के नाते विशाल देश में प्रवेश के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा के दौर में सफलता को सुनिश्चित करने के लिए शॉर्टकट अपनाने को हर कोई मचल रहा है। नीट डाक्टरी के लिए प्रवेश द्वार और धनार्जन का प्रबल उपाय। चाहे जैसे हो और पात्रता भी हो न हो अपनी सीट सुरक्षित करवाने की धुन छात्रों और उनके माता-पिता कुछ भी धन और धर्म दोनों की क़ुरबानी देने के लिए उद्यत रहते हैं। लीक हुआ पेपर लाखों में बिका और इस व्यवसाय की कमाई बेइंतहा है। पेपर लीक की जो कथा उभर रही है वह बेईमानी की कई-कई परतों को खोल रही है। वह समाज में मूल्यों के क्षरण को व्यक्त करती है। यह तमाम तरह के शॉर्टकट से जुड़ी हुई है जो समाज को दीमक की तरह खा रहे हैं। ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता जिस तरह से गिर रही है। ऐसे में सफलता के लिए आतुर समाज में इस तरह की नैतिक दुर्घटनाएं स्वाभाविक हैं। आज सभी दल शिक्षा पर बात कर रहे हैं, पर गंभीरता किसी के दिल दिमाग में है, यह संदेहास्पद है। मंत्री का इस्तीफा देना या लेना प्रतीकात्मक असर वाला होगा, पर शिक्षा सुधार की कुंजी तो नहीं ही है। व्यापक राजनीतिक फ़सल काटने की ताक में सभी जरूर हैं। शिक्षा के सवाल क्या हैं और उनको समझने की कोशिश करने की बात कोई नहीं कर रहा। अगर मंत्री के सिवाय सब कुछ वही रहे, यथावत, तो क्या पेपर लीक की समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या पेपर्स लीक ग़लत है पर क्या वही शिक्षा की सारी समस्याओं की जड़ है? गौर करने की बात है। पेपर का लीक होना कोई स्वतंत्र समस्या नहीं है। आज कोई तत्काल कमाई करने के लिए तो कोई भविष्य की कमाई की राह बनाने के लिए ईमानदारी को बिना किसी संकोच के तिलांजलि दे रहा है। इसी के समानांतर पैसा देकर नौकरी देने और पाने की चेष्टा भी हो रही है। रुपया लेकर काम यानी सुविधा-शुल्क जग जाहिर बात है। जाने कितने आफिस ऐसे हैं जहाँ बिना किसी तरह की सिफारिश या घूस या दोनों के बिना कोई कागज टस से मस नहीं होता। धन के अवैध यातायात के साथ न्यायालय का बड़ा घनिष्ठ रिश्ता है इसके कई उदाहरण आ चुके हैं। न्याय कितनी मुश्किल और कितनी मंहगी प्रक्रिया से होता है वह कोर्ट के दरवाजे जाने वाले से पूछिए। क़ानूनी प्रक्रियाओं का हाल ऐसा है कि उनके उलझन में कोई राह नहीं मिलती। प्रतिदिन राजनीति प्रेरित कितने मुक़दमे चलते हैं और कितने बरी हो जाते हैं, इसका हिसाब लगाना मुश्किल है। फ़ास्ट ट्रैक की कचहरी किन-किन चीजों के लिए लगेगी? रसूख़ वाले और पैसेदार नेताओं और अन्य लोगों के मुक़दमों की गिनती ही नहीं होती। जबकि आम जन उसमें पिसने के लिए मजबूर हैं। पर यह सब वर्तमान चर्चा में सीधे-सीधे प्रासंगिक नहीं है। शिक्षा ही विकास का मूल है और इसी से आत्मनिर्भरता भी आएगी पर इसके लिए शिक्षा को स्वायत्तता देनी होगी और शिक्षकों पर भरोसा भी करना होगा। शिक्षा के मार्ग में अनेक समस्याएं मुंह बाये खड़ी हैं। शिक्षा की जो विसंगतियां मुँह बाये खड़ी हैं उसके लिए जंतर-मंतर की राजनीति से ही काम नहीं चलेगा। आठ दशक से उपनिवेश की हैसियत से स्वतंत्र हुए देश में पाश्चात्य शिक्षा पर ही हम आश्रित बने हुए हैं। अब नवउदारवाद की गुलामी का शिकंजा कसा जा रहा है । यह अच्छी बात है कि हमारे मान्यवरों की नींद टूटी है और उनकी दृष्टि में शिक्षा आ रही है। इसलिए शिक्षा की पीड़ा को उन्हें याद दिलाना ठीक होगा। यहाँ संक्षेप में प्रमुख मुद्दों का उल्लेख करना जरूरी लग रहा है। आज शिक्षा का बुनियादी ढांचा कमजोर हो रहा है। शिक्षा महंगी होती जा रही है। शिक्षा में सृजनात्मकता की जगह आज भी रटने पर ही ज़ोर है।

हमारी शिक्षा का संस्कृति और मूल्य से रिश्ता कमजोर है। कोचिंग का व्यापार तेजी से उठान पर है। कोचिंग संस्थान की ओर नज़र तब जाती है जब कोई दुर्घटना होती है परंतु देश के राष्ट्रीय दैनिक अखबारों के मुखपृष्ठ आए दिन इनके विज्ञापनों से सुशोभित होते हैं। स्कूल-कॉलेज में दाखिला महाभारत से कम नहीं होता। दाखिले से लेकर परीक्षा तक की यात्रा हर आम आदमी के लिए युद्ध का मोर्चा बना हुआ है। विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की कमी वर्षों से बनी हुई है । शिक्षा को बजट में कभी भी वायदे के मुताबिक छह प्रतिशत का हिस्सा नहीं मिल पाता जिसके कारण शिक्षा-संस्थानों में सुविधाओं का लगातार अभाव बना हुआ है। अमीरी-गरीबी का भेद शिक्षा की दुनिया में बेतहाशा बढ़ता जा रहा है जहाँ प्राइमरी स्तर पर मुफ्त से लेकर हजारों रूपये महीने की फ़ीस वाले स्कूल चल रहे हैं। इसी तरह निजी विश्वविद्यालय मनचाही फीस वसूल रहे हैं। शिक्षा पर ईमानदारी के साथ अपनी जमीन पर खड़े होकर समाधान खोजने की जरूरत है।

राम मंदिर ट्रस्ट सीईओ के लिए अनावश्यक शर्त

श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदकों की बड़ी संख्या को देखते हुए फिलहान नियुक्ति को कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दिया है, लेकिन इसे लेकर कुछ सवाल भी उठे हैं। आवेदन से जुड़ी अपेक्षाओं में सीईओ के कर्तव्यों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये श्रेणिया हैं-मुख्य परिचालन एवं प्रशासनिक कर्तव्य, तीर्थयात्री प्रबंधन तथा सुरक्षा और सांस्कृतिक एवं संस्थागत संरक्षण।

विवेक काटज

पहली दो श्रेणियां विशुद्ध प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रकृति की हैं। जबकि तीसरी श्रेणी धार्मिक अनुष्ठान पर्यवेक्षण के अंतर्गत यह उल्लेख है कि 'धार्मिक अनुष्ठानों, उत्सवों और मंदिर समारोहों के सुचारु, व्यवस्थित एवं पारंपरिक संचालन को सुगम और सुनिश्चित करना।' सीईओ से यह भी अपेक्षा होगी कि वह उन पुजारियों-पुरोहितों को वे सभी आवश्यक सुविधाएं एवं सहयोग प्रदान करे, जो ऐसे समारोहों का संचालन करते हैं। ऐसी अपेक्षा इसलिए, क्योंकि इन कार्यक्रमों की प्रकृति पूरी तरह धार्मिक होगी, जिनके लिए उसके पास आवश्यक विशेषज्ञता का संभवतः अभाव होगा। सीईओ के लिए निकले विज्ञापन में 'सक्रिय हिंदू' होना अनिवार्य किया गया है। इस अनिवार्यता में कोई बुराई नहीं कि सीईओ को हिंदू होना ही चाहिए, लेकिन इसका दूसरा पहलू कुछ चिंतित करने वाला है। पिछले पांच सौ वर्षों के दौरान हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों के मतभेदों को दूर करने की दिशा में जो भी प्रगति हुई है, यह प्रविधान उसे पलटने की आशंका लिए हुए है। यहां तक कि यह भाव श्रीराम के अनन्य भक्तों में से एक गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस में व्यक्त भावना के भी विपरीत है। यह बात अब लगभग विस्मृत कर दी गई है कि तुलसीदास के समय में शैव और वैष्णव भक्तों के बीच गहरा मतभेद और वैमनस्य था। यह प्रतिद्वंद्विता आज भी देश के कुछ हिस्सों में मौजूद है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों से यह काफी हद तक समाप्त हो चुकी है। इसलिए इस पर आश्चर्य हुआ कि राम मंदिर में सीईओ के लिए किसी 'वैष्णव' को प्राथमिकता देने का उल्लेख क्यों था? जब हिंदुओं को विभाजित करने वाली कोई बात मुझे व्यथित करती है तो स्मृति बचपन के दिनों की ओर लौट जाती है और मुझे दो मित्र-भाई याद आते हैं। इनमें से एक सेवानिवृत्त आइएएस हैं और दूसरे एक वरिष्ठ वकील। दोनों ही श्रीराम के परम भक्त हैं और रामचरितमानस के मर्मज्ञ। जब मैंने सीईओ पद पर नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में 'रामभक्त वैष्णव' को प्राथमिकता की ओर उनका ध्यान आकर्षित कराया तो उन्होंने जवाब में मुझे रामचरितमानस की कई ऐसी चौपाइयां और दोहे भेजे, जिनमें यह उल्लेख है कि स्वयं प्रभु श्रीराम भगवान शिव के विषय में क्या कहते हैं, 'सिव द्रोही मम भगत कहावा।

सो नर सपनेहु मोहि न पावा॥ संकर बिमुख भगति चह मोरी। सो नारकी मूढ़ मति थोरी॥ ऐसा ही एक उदाहरण भगवान श्रीराम के अयोध्यावासियों को संबोधन का है, जिसमें वे कहते हैं, 'औरउ एक गुपुत मत सबहि कहउं करि जोरि। शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोरि॥' श्रीराम और महादेव के मध्य किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं और इसकी पुष्टि स्वयं दोनों के उद्गार करते हैं। 'उमा कहउं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजनु जगत् सब सपना॥' जैसे दोहे के रूप में व्यक्त हुआ ऐसा ही एक भाव करोड़ों हिंदुओं के हृदय में बसा हुआ है। जब स्वयं गोस्वामी तुलसीदास ने भक्ति भाव को लेकर ऐसे किसी विभाजन की राह को इतने प्रभावी ढंग से अवरुद्ध कर दिया कि आज शैव और वैष्णव के बीच अंतर की कोई बात नहीं करता, तब राम मंदिर के सीईओ के लिए 'वैष्णव' को प्राथमिकता देने की शर्त की भला क्या ही आवश्यकता थी? यह संभव है कि देश के कुछ हिस्सों में हिंदू समाज के बीच यह भेद अभी भी कुछ हद तक कायम हो, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्रों में आम हिंदू बिना ऐसे किसी आग्रह के सभी मंदिरों में अपनी आस्था के साथ श्रद्धानवत होते हैं। एक सामान्य श्रद्धालु प्रभु श्रीराम, देवाधिदेव महादेव और आदिशक्ति देवी के विभिन्न रूपों-स्वरूपों की पूजा-अर्चना समान भाव से करता है और लोग स्वयं को शैव, वैष्णव या शाक्त (देवी-भक्त) कसौटियों पर कसते हुए एक-दूसरे के साथ कोई भेद नहीं करते। यह दलील दी जा सकती है कि राम मंदिर में पूजा-पाठ करने वाले पुरोहित वैष्णव परंपरा के होने चाहिए, क्योंकि वही सभी रीतियों से भलीभांति परिचित होंगे, लेकिन यही पैमाना सीईओ पर लागू नहीं किया जा सकता। जब सरकार ने आइएएस अधिकारियों को प्रारंभिक ट्रस्ट का सदस्य बनाया और उन्हें इतने महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे तब क्या उनके लिए 'वैष्णव' होने की शर्त को वांछनीय माना गया था? प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से ऐसी किसी धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा करना संवैधानिक और प्रशासनिक मर्यादा के भी विपरीत है। यह स्थिति तब और भी विरोधाभासी लगती है, जब स्वयं प्रभु श्रीराम और महादेव दोनों ने ही अपने-अपने भक्तों को एक-दूसरे का अनादर न करने की स्पष्ट चेतावनी दी है। हाल के घटनाक्रमों के चलते अयोध्या के राम मंदिर पर देश-दुनिया की निगाहें टिकी हैं। भले ही इसके निर्माण की राह सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय से प्रशस्त हुई हो, लेकिन प्रभु श्रीराम के जन्मस्थान पर एक भव्य मंदिर करोड़ों हिंदुओं का स्वप्न रहा है और उसके साकार होने के बाद यह उनकी आस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण और भव्य प्रतीक बन चुका है। इसलिए ट्रस्ट को न केवल वित्तीय और प्रशासनिक मामलों में बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है, बल्कि उसे इसका भी विशेष ध्यान रखना होगा कि वह जाने-अनजाने ऐसे कोई संकेत न दे, जिससे हिंदुओं के बीच सदियों पहले गिर चुकी विभाजन की कोई दीवार फिर से खड़ी हो जाए। ट्रस्ट को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि सीईओ पद के लिए किसी व्यक्ति के 'वैष्णव' होने को वांछनीय बताने वाली शर्त वापस ली जाए। वैसे तो आवेदन की अंतिम तिथि बीत चुकी है, फिर भी यदि ट्रस्ट चाहे तो इस शर्त को हटाने का कोई रास्ता निकाल सकता है।

मंदसौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई ! स्कॉर्पियो से 465 किलोग्राम डोडाचूरा बरामद, 21 लाख 30 हजार रुपए से अधिक की सामग्री जब्त

मीडिया ऑडीटर, मंदसौर (निप्र)। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा प्रदेशभर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, भंडारण और बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंदसौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है थाना अफजलपुर पुलिस ने एक संदिग्ध स्कॉर्पियो वाहन से 465 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा बरामद कर वाहन सहित लगभग 21 लाख 30 हजार रुपए से अधिक मूल्य की सामग्री जब्त की है पुलिस कार्रवाई के दौरान तस्कर मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मंदसौर विनोद कुमार मीणा के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेरसिंह बघेल के निर्देशन में थाना अफजलपुर पुलिस द्वारा की गई। पुलिस के अनुसार 24 जुलाई की रात थाना अफजलपुर पुलिस क्षेत्र में नियमित गश्त कर रही थी और संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही थी इसी दौरान पुलिस टीम को एक स्कॉर्पियो वाहन संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया पुलिस ने वाहन को रोकने का प्रयास किया लेकिन चालक ने वाहन की गति बढ़ा दी और भागने का प्रयास किया पुलिस टीम द्वारा पीछा किए जाने पर चालक कुछ दूरी तक वाहन लेकर गया और फिर अंधेरे का फायदा उठाकर वाहन छोड़कर फरार हो गया पुलिस ने मौके पर वाहन को कब्जे में लेकर उसकी तलाशी ली तलाशी के दौरान स्कॉर्पियो के अंदर से बड़ी मात्रा में डोडाचूरा बरामद हुआ पुलिस ने बताया कि वाहन में 21 कट्टों में भरा 465 किलोग्राम डोडाचूरा रखा हुआ था बरामद मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 9 लाख 30 हजार रुपए बताई गई है इसके अलावा तस्करी में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन की कीमत लगभग 12 लाख रुपए आंकी गई है इस प्रकार पुलिस ने कुल मिलाकर करीब 21 लाख 30 हजार रुपए की संपत्ति जब्त की है मामले में थाना अफजलपुर में एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है पुलिस अब फरार आरोपियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास में जुटी हुई है इसके लिए पुलिस की विशेष टीमें सक्रिय कर दी गई हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है तस्करी परिवहन, भंडारण और बिक्री में शामिल लोगों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा गौरतलब है कि मंदसौर जिला लंबे समय से मादक पदार्थों की अवैध गतिविधियों को लेकर संवेदनशील माना जाता रहा है। इसी को देखते हुए पुलिस द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों, प्रमुख मार्गों और संदिग्ध गतिविधियों वाले स्थानों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है वाहन जांच, गश्त और मुखबिर तंत्र के माध्यम से अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि किसी क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की गतिविधियों की जानकारी मिलती है तो तत्काल पुलिस को सूचना दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। मध्यप्रदेश पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी वैध मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी पुलिस का उद्देश्य प्रदेश में नशे के अवैध नेटवर्क को समाप्त कर युवाओं और समाज को इसके दुष्प्रभावों से बचाना है।

मनेन्द्रगढ़ की सड़कों पर आवारा मवेशियों का कब्जा, एनएच-43 पर बढ़ा दुर्घटना का खतरा

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में आवारा मवेशियों की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। शहर के राष्ट्रीय राजमार्ग-43 (एनएच-43) सहित प्रमुख सड़कों, बाजारों और चौक-चौराहों पर मवेशियों के झुंड बैठे और घूमते नजर आ रहे हैं जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है स्थानीय नागरिकों के अनुसार सड़कों पर मवेशियों के बैठने से वाहन चालकों को अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। रात के समय यह समस्या और बढ़ जाती है क्योंकि अंधेरे में सड़क पर बैठे मवेशी आसानी से दिखाई नहीं देते लोगों का कहना है कि नगर पालिका को कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है शहर के एकमात्र गौठान में पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में मवेशी खुले में घूम रहे हैं नागरिकों ने जिला प्रशासन और नगर पालिका से मांग की है कि आवारा मवेशियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए उन्होंने कहा कि यदि जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो किसी बड़े सड़क हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता शहरवासियों ने यातायात व्यवस्था सुधारने और दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई की मांग की है।

कोतवाली पुलिस ने युवाओं को दिया नशामुक्ति का संदेश, टीआई ने पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ किया भोजन

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। जिले में चलाए जा रहे 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' जनजागरूकता अभियान के तहत शनिवार को कोतवाली थाना पुलिस द्वारा पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा बलों में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए नशामुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया कार्यक्रम का आयोजन फास्ट ट्रैक फिजिकल अकादमी में किया गया, जहां बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने भाग लिया कार्यक्रम में कोतवाली थाना प्रभारी रोहित दुबे ने युवाओं को संबोधित करते हुए नशे के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी उन्होंने कहा कि पुलिस और सुरक्षा बलों में सेवा के लिए अनुशासन, शारीरिक क्षमता और मानसिक मजबूती बेहद जरूरी होती है नशे की आदत इन सभी क्षमताओं को प्रभावित करती है और युवाओं के भविष्य के लिए बाधा बन सकती है थाना प्रभारी ने युवाओं से कहा कि यदि वे अपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसी हर आदत से दूरी बनानी होगी जो उनकी सफलता के रास्ते में रुकावट पैदा करती है उन्होंने स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, नियमित अभ्यास करने और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों ने सभी छात्र-छात्राओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई साथ ही युवाओं से अपील की गई कि वे स्वयं नशामुक्त रहें और अपने परिवार तथा समाज के अन्य लोगों को भी नशे के खिलाफ जागरूक करें कार्यक्रम में अकादमी के प्रशिक्षकों ने भी युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता के लिए मेहनत, अनुशासन और नियमित दिनचर्या सबसे महत्वपूर्ण है उन्होंने छात्रों को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने की सलाह दी कार्यक्रम के बाद थाना प्रभारी रोहित दुबे, उपनिरीक्षक सुमित शर्मा, आरक्षक अंकित शर्मा, आरक्षक शरद यादव सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने अकादमी के प्रशिक्षुओं के साथ बैठकर भोजन किया इस दौरान छात्रों ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया, तैयारी के तरीके और पुलिस सेवा से जुड़े अनुभवों को लेकर अधिकारियों से चर्चा की पुलिस और युवाओं के बीच हुए इस संवाद से छात्रों को प्रेरणा मिली। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल नशे के प्रति जागरूकता फैलाना नहीं बल्कि युवाओं को सही दिशा देकर उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रेरित करना भी है शिवपुरी पुलिस ने आगे भी इस प्रकार के जनजागरूकता कार्यक्रम जारी रखने की बात कही है।

दो माह से राशन नहीं मिलने पर ग्रामीण पहुंचे एसडीएम कार्यालय, सेल्समैन पर फिंगरप्रिंट लेकर राशन रोकने का आरोप

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। जिले के पिछोर अनुविभाग अंतर्गत ग्राम पंचायत ढला में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी सामने आई है शनिवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचे और राशन दुकान के सेल्समैन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की ग्रामीणों ने राशन दुकान संचालक अखिलेश मिश्रा पर आरोप लगाया कि पिछले दो महीने से हितग्राहियों को राशन का वितरण नहीं किया जा रहा है ग्रामीणों का कहना है कि जब वे राशन लेने दुकान पर पहुंचते हैं तो उन्हें यह कहकर वापस कर दिया जाता है कि अभी राशन उपलब्ध नहीं है शिकायत में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि राशन नहीं मिलने की बात कहने पर सेल्समैन द्वारा कथित रूप से धमकी दी जाती है कि शिकायत करने से भी कोई फायदा नहीं होगा और राशन नहीं मिलेगा ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि सेल्समैन ने रात के समय कुछ लोगों को बुलाकर केवाईसी के नाम पर उनके फिंगरप्रिंट लिए, लेकिन इसके बाद भी राशन उपलब्ध नहीं कराया गया ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कई ऐसे हितग्राही हैं जो अशिक्षित हैं और उन्हें राशन वितरण प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं होती आरोप है कि ऐसे लोगों से भी फिंगरप्रिंट लिए गए लेकिन उन्हें खाद्यान्न नहीं दिया गया ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में पहले भी शिकायत की गई थी लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई उनका आरोप है कि सेल्समैन के प्रभाव के कारण कई गरीब परिवार अपनी समस्या खुलकर नहीं रख पा रहे हैं एसडीएम कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए साथ ही उन्होंने राशन दुकान संचालक को हटाने की भी मांग रखी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे परिवार सहित सड़क पर बैठकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी ग्रामीण रूपेश योगी ने बताया कि गांव के कई परिवारों को लगातार दो महीने से राशन नहीं मिला है। वहीं लोकेश लोधी ने आरोप लगाया कि कई हितग्राहियों से केवाईसी के नाम पर फिंगरप्रिंट तो लिए गए, लेकिन राशन वितरण नहीं किया गया। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की जांच कर गरीब हितग्राहियों को उनका हक दिलाने की मांग की है।

किसानों के भोपाल कूच से पहले प्रशासन सक्रिय, प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री से मुलाकात की तैयारी

मीडिया ऑडीटर, नर्मदापुरम (निप्र)। शत-प्रतिशत मूंग खरीदी और खाद वितरण की ई-टोकन व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के प्रस्तावित भोपाल कूच से पहले प्रशासन सक्रिय हो गया है 27 जुलाई को भोपाल में मुख्यमंत्री आवास घेराव की घोषणा के बीच शनिवार को जिला प्रशासन ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर समाधान निकालने का प्रयास किया नर्मदापुरम के सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में कलेक्टर सोमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक साईं कृष्णा एस थोटा ने संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों से चर्चा की करीब 45 मिनट चली बैठक में प्रशासन की ओर से किसान प्रतिनिधिमंडल को 26 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कराने का प्रस्ताव दिया गया बैठक में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रखीं। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों ने बताया कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान शत-प्रतिशत मूंग खरीदी, ई-टोकन प्रणाली की जटिल प्रक्रिया में बदलाव, खाद वितरण व्यवस्था सहित अन्य किसान समस्याओं को प्रमुखता से रखा जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पटवारे और राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के प्रदेश मंत्री रमाकांत मीणा ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री के साथ चर्चा में किसानों की मांगों पर सहमति नहीं बनती है तो 27 जुलाई को प्रस्तावित भोपाल कूच किया जाएगा उन्होंने कहा कि हजारों किसान मां नर्मदा का पूजन कर नर्मदापुरम से भोपाल के लिए पैदल मार्च शुरू करेंगे। बताया गया कि संयुक्त किसान मोर्चा ने इससे पहले 20 जुलाई को नर्मदापुरम संभागायुक्त श्रीकांत बनोट को ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात कराने की मांग की थी तय समय तक मुलाकात नहीं होने के बाद किसान संगठनों ने पैदल मार्च की तैयारियां तेज कर दी थीं प्रशासन द्वारा बुलाई गई बैठक में एडीएम, एसडीएम, कृषि उप संचालक सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं किसान संगठनों की ओर से क्रांतिकारी किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लीलाधर राजपूत, जिला अध्यक्ष हरपाल सिंह सोलंकी, भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राजेश जाट, संभागीय अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार गौर सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। गौरतलब है कि संयुक्त किसान मोर्चा की रणनीति बैठक 19 जुलाई को इटारसी के मेहरागांव स्थित देवाशीष गार्डन में आयोजित की गई थी। इसमें नर्मदापुरम सहित हरदा, बैतूल, खंडवा, सीहोर, नरसिंहपुर और खरगोन जिलों के किसान नेताओं ने भाग लिया था। बैठक में भोपाल कूच, रेल रोको और अन्य लोकतांत्रिक आंदोलनों को लेकर रणनीति तैयार की गई थी अब सभी की नजर मुख्यमंत्री के साथ होने वाली किसान प्रतिनिधिमंडल की बैठक पर है किसानों का कहना है कि मांगों का समाधान नहीं होने पर आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा।

एमसीबी में कायस्थ समाज ने किया प्रतिभाओं का सम्मान, NEET में सफल 6 विद्यार्थियों का अभिनंदन

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिला मुख्यालय में शनिवार को कायस्थ महासभा एवं ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस (जीकेसी) के संयुक्त तत्वावधान में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। चित्रगुप्त, अंबिका एवं गणेश मंदिर परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में NEET परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले जिले के छह मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। समारोह में सफल विद्यार्थियों को तिलक लगाकर, मिठाई खिलाकर, स्मृति-चिन्ह (मोमेंटो) और कलम भेंट कर सम्मानित किया गया समाज के वरिष्ठजनों ने विद्यार्थियों की उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत होती है प्रतिभाओं का सम्मान करने से अन्य विद्यार्थियों को भी आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य हासिल करने की प्रेरणा मिलती है कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि हृश्वश्वञ्ज जैसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल करना विद्यार्थियों की मेहनत, लगन और निरंतर प्रयासों का परिणाम है उन्होंने विश्वास जताया कि सम्मानित विद्यार्थी भविष्य में चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं देकर समाज, जिले और देश का नाम रोशन करेंगे। सम्मानित विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, गुरुजनों और नियमित अध्ययन को दिया उन्होंने कहा कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अनुशासित दिनचर्या, समय का सही प्रबंधन, आत्मविश्वास और लगातार अभ्यास बेहद जरूरी है विद्यार्थियों ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं से धैर्य बनाए रखने और मेहनत करते रहने की अपील की समारोह में कायस्थ समाज के पदाधिकारी, वरिष्ठजन, महिलाएं, युवा और अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। समाज के लोगों ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने कायस्थ महासभा और ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस (जीकेसी) के पदाधिकारियों सहित उपस्थित सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि प्रतिभा सम्मान समारोह का उद्देश्य केवल उपलब्धि हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सम्मान देना नहीं, बल्कि नई पीढ़ी को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करना भी है। एमसीबी जिले में पहली बार कायस्थ समाज द्वारा हृश्वश्वञ्ज में सफल विद्यार्थियों का सार्वजनिक सम्मान किया गया, जिसे समाज के लोगों ने एक प्रेरणादायी पहल बताया।

शिवपुरी में नर्स से जेवर और नकदी की ठगी, तीन बदमाशों ने झांसे में लेकर पर्स कराया खाली

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। शहर में दिनदहाड़े ठगी की वारदात सामने आई है जिला अस्पताल में पदस्थ एक नर्स को तीन अज्ञात बदमाशों ने बातों में उलझाकर धमकाया और उसके सोने के जेवर व नकदी लेकर फरार हो गए पीड़िता ने कोतवाली थाना पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है पुलिस ने जांच शुरू कर दी है जानकारी के अनुसार घटना शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे की है कस्टम गेट निवासी किरण राठौर (पत्नी सूरज प्रसाद राठौर) जिला अस्पताल में ड्रेसिंग ड्यूटी के लिए जा रही थीं इसी दौरान डाक बंगले के सामने स्थित छब्बर स्कूल के पीछे बाइक सवार तीन अज्ञात युवकों ने उन्हें रोक लिया पीड़िता के अनुसार आरोपियों ने पहले सामान्य बातचीत कर उन्हें अपने झांसे में लिया, इसके बाद डराने-धमकाने लगे बदमाशों ने नर्स से गले में पहना सोने का मंगलसूत्र, कानों की कनौती, सोने की सुई-धागा सहित अन्य जेवर उतारकर पर्स में रखने को कहा धमकी के कारण नर्स ने अपने जेवर पर्स में रख दिए पर्स में पहले से करीब 4 हजार रुपए नकद भी रखे हुए थे इसके बाद आरोपियों ने पर्स अपने साथी को दे दिया और नर्स को 11 कदम आगे चलने के लिए कहा जैसे ही वह आगे बढ़ीं, तीनों आरोपी पर्स लेकर मौके से फरार हो गए घटना के बाद पीड़िता ने कोतवाली थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है वहीं, शहर में ठगी की एक अन्य घटना भी सामने आई है पोहरी बस स्टैंड क्षेत्र में चार बदमाशों ने एक युवक को सस्ते दामों में सोने-चांदी के आभूषण देने का लालच देकर 13 हजार रुपए ठग लिए और नकली जेवर थमाकर फरार हो गए।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर नर्मदापुरम कांग्रेस का विजय जुलूस, बारिश के बीच कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

मीडिया ऑडीटर, नर्मदापुरम (निप्र)। नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नर्मदापुरम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकालकर खुशी जाहिर की जिला एवं नगर कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आयोजित इस रैली में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे छात्रों, युवाओं और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग करने वालों की जीत बताया विजय जुलूस शहर के सतरस्ते से प्रारंभ होकर गांधी प्रतिमा स्थल तक निकाला गया जुलूस के दौरान मौसम खराब रहा और बीच-बीच में रिमझिम बारिश भी हुई, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ बारिश के बीच कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए रैली निकाली और अपनी खुशी का इजहार किया कार्यक्रम का नेतृत्व जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष फैजान उल हक ने किया इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे कार्यकर्ताओं ने हाथों में कांग्रेस के झंडे लेकर शहर में रैली निकाली और शिक्षा व्यवस्था में सुधार तथा छात्रों के अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की जुलूस के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 'छात्रों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में', 'छात्र संगठन जिंदाबाद', 'भारत माता की जय', 'वंदे मातरम' और 'राहुल गांधी जिंदाबाद' सहित कई नारे लगाए कार्यकर्ताओं ने कहा कि नीट परीक्षा से जुड़े विवादों और कथित अनियमितताओं के कारण देशभर के लाखों विद्यार्थियों में असंतोष था उन्होंने दावा किया कि छात्रों और युवाओं द्वारा लगातार उठाई जा रही आवाज के परिणामस्वरूप यह कदम सामने आया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाएं युवाओं के भविष्य से जुड़ी होती हैं। इनमें किसी भी प्रकार की अनियमितता से मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के साथ अन्याय होता है उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में विश्वास बनाए रखने के लिए परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाना आवश्यक है विजय जुलूस में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से मांग की कि परीक्षा प्रणाली को मजबूत किया जाए, पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए और विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि युवाओं के भविष्य और शिक्षा के अधिकार से जुड़े मुद्दों को लेकर पार्टी लगातार संघर्ष करती रहेगी।

सिंगरौली: एनएच-39 पर ट्रेलर चालक का शव मिला

पानी भरे गड्ढे में पड़ी थी लाश, दाहिने पैर पर चोट के निशान

मीडिया ऑडीटर,सिंगरौली (निप्र)। सिंगरौली जिले के बरगवां थाना क्षेत्र में शनिवार को एनएच-39 पर एक ट्रेलर चालक का शव पानी से भरे गड्ढे में मिला। त्रिमुला कंपनी के मुख्य गेट के सामने हुई इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। राहगीरों ने शव को तैरता देख पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने शव को गड्ढे से बाहर निकाला और जांच शुरू की।

मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के बभनी थाना क्षेत्र स्थित सागो बांध निवासी दुर्योधन यादव के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दुर्योधन कोयले से भरा ट्रेलर लेकर खड़िया से महान कंपनी की ओर जा रहा था। त्रिमुला कंपनी गेट के पास संदिग्ध परिस्थितियों में उसका शव पानी भरे गड्ढे में मिला। मृतक के दाहिने पैर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं, जिससे पुलिस मामले को संदिग्ध मान रही है।

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने एनएच-39 की खराब हालत पर नाराजगी व्यक्त की। उनका आरोप है कि त्रिमुला गेट के पास सड़क पर लंबे समय से

बड़े-बड़े गड्ढे हैं, जिनमें बारिश का पानी भर जाता है। स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे कुछ ढाबों पर डीजल चोरी और अवैध शराब बिक्री जैसी गतिविधियों का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि प्रशासन की अनदेखी के कारण इस क्षेत्र में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं।

बरगवां थाने से मौके पर पहुंचे सब इंस्पेक्टर सूरत सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिलते ही टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। शव का पंचनामा कर उसे कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है और अन्य ट्रेलर चालकों से भी पूछताछ की जा रही है। मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। पुलिस इसे संदिग्ध मौत मानकर सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।

सब इंस्पेक्टर सिंह ने आगे बताया कि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही हो सकेगा। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

गुरुपूर्णिमा और सावन पर रेलवे का बड़ा फैसला, सीहोर स्टेशन पर 10 जोड़ी ट्रेनों का अस्थायी ठहराव, 30 जुलाई तक लागू रहेगी विशेष व्यवस्था

मीडिया ऑडीटर,सीहोर (निप्र)। गुरुपूर्णिमा महोत्सव और सावन माह के दौरान सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम सहित अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने सीहोर रेलवे स्टेशन पर गुजरने वाली 10 जोड़ी मेल, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों का अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है। रेलवे के इस फैसले से मध्यप्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को सीहोर पहुंचने में काफी सुविधा मिलेगी।

30 जुलाई तक लागू रहेगी विशेष व्यवस्था: पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि यह विशेष व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है और 30 जुलाई तक प्रभावी रहेगी। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए ट्रेनों के संचालन में यह अस्थायी बदलाव किया गया है।रेलवे का कहना है कि यदि आवश्यकता हुई तो यात्रियों की संख्या और परिस्थितियों की समीक्षा के बाद आगे भी आवश्यक निर्णय लिए जा सकते हैं।

कुबेरेश्वर धाम में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़: सावन और गुरुपूर्णिमा के दौरान सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। सप्ताहांत और विशेष पर्वों पर यह संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। इसी को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराते हुए प्रमुख ट्रेनों का अस्थायी ठहराव स्वीकृत किया है, ताकि यात्रियों को भोपाल या अन्य स्टेशनों पर उतरकर अतिरिक्त सफर न करना पड़े।

पवन चक्की पर डकैती डालने के पहले पकड़ाएं 8 बदमाश

खंडहर में बैठ बना रहे थे प्लानिंग, हथियार, इलेक्ट्रॉनिक कटर और 5 किलो गांजा बरामद

मीडिया ऑडीटर, रतलाम (निप्र)। रतलाम के बिलपांक थाना अंतर्गत पवन चक्कियों पर डकैती की योजना बना रहे 8 बदमाशों को पकड़ा है। एक आरोपी नाबालिग है। इनके पास से हथियार समेत इलेक्ट्रॉनिक कटर व 5 किलो से अधिक गांजा भी मिला है।

पुलिस ने बदमाशों को 23 जुलाई की रात पकड़ा। 24 जुलाई की रात पुलिस ने बदमाशों का खुलासा किया। बिलपांक थाना प्रभारी अयुब खान ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि महू-नीमच रोड फोरलेन पर सरवड़ के पास स्थित एक खंडहर में 08 बदमाश को हथियारों के साथ बैठे है। बदमाश में पास में स्थित पवन चक्की पर डकैती डालने की योजना बना रहे है। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी। रतलाम ग्रामीण एसडीओपी किशोर पाटनवाला व थाना प्रभारी बिलपांक अयुब खान द्वारा पुलिस

टीम बनाकर घेराबंदी की। पुलिस टीम ने मौके पर 8 व्यक्तियों को संदिग्ध अवस्था में एक जह मिले। जो पवन चक्की पर डकैती डालने

डकैती कर बोलेरो से भागने वाले थे

बदमाशों क्षेत्र में बोलेरो वाहन क्रमांक एमपी 09 सीपी 0586 से पहुंचे थे। जो पुलिस को मौके पर मिली। डकैती के बाद इसी बोलेरो वाहन से भागने की योजना थी। पुलिस ने इनके पास से 2 धारदार तलवार, 05 दरांते, 1 इलेक्ट्रॉनिक कटर समेत 5.428 किलोग्राम गांजा भी बरामद किया गया। इसके अलावा मौके से शराब के खाली क्वार्टर, बीड़ी के बंडल, डिस्पोजल एवं पानी की खाली बोतलें भी बरामद की है।

● बदमाशों में एक नाबालिग शामिल

विनोद (19)पिता गौतम डिण्डोर, अनिल (19)पिता प्रभु मईड़ा, कैलाश (25)पिता जोखा निनामा, संदीप (26) पिता धारासिंह निनामा, रामलाल (28)पिता जीवन निनामा सभी निवासी ग्राम आम्बापाड़ा, थाना सरवन, जिला रतलाम, सुरेंद्र मईड़ा (21)पिता पुंजा मईड़ा निवासी ग्राम रामगढ़, थाना आम्बापुरा, जिला बांसवाड़ा (राजस्थान), सतीश (26)पिता कालू कटारा, निवासी ग्राम जमुनिया, थाना सरवन, जिला रतलाम व एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है।

प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों द्वारा पास स्थित पवन चक्की पर डकैती डालने की योजना

सेल्फी लेकर कार से आगे बढ़ा परिवार, ट्रक ने कुचला

यूपी की महिला की मौत, बच्चे समेत 4 गंभीर, ओंकारेश्वर दर्शन कर लौट रहे थे रिश्तेदार

मीडिया ऑडीटर,खंडवा (निप्र)। मध्यप्रदेश के खंडवा में इंदिरा सागर बांध के पास फोटो और सेल्फी लेकर परिवार कार में बैठा। कार आगे बढ़ी ही थी कि राखड़ (फ्लाई ऐश) से भरे ट्रक ने उसे रौंद दिया। कार में उत्तर प्रदेश के 11 श्रद्धालु सवार थे। हादसे में लखनऊ निवासी 80 वर्षीय कलावती की मौत हो गई। बच्चे समेत कई लोग घायल हैं। इनमें चार की हालत गंभीर है।

टक्कर इतनी भीषण थी कि कार ट्रक के नीचे जा फंस गई। उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए। हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला गया। ड्राइवर को दरवाजा तोड़कर निकाला गया।

मां-बेटे की हालत गंभीर, इंदौर रेफर:

घायलों को पहले इंदिरा सागर बांध अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद सभी को पुनासा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया गया। यहां से गंभीर रूप से घायल अमित गुप्ता और उसकी मां ममता को इंदौर रेफर किया गया।

अमित गोरखपुर का रहने वाला है। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। अन्य घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।

महाकाल दर्शन के बाद पहुंचे थे ओंकारेश्वर:

परिजनों ने बताया कि सभी लोग आपस में रिश्तेदार हैं। कोई लखनऊ, कोई गोरखपुर तो कोई बनारस का रहने वाला है। सभी धार्मिक यात्रा पर निकले थे।

पहले उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए। इसके बाद ओंकारेश्वर पहुंचे। नर्मदा स्नान और ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद सीहोर के कुबेरेश्वर धाम जा रहे थे।

इंदिरा सागर डैम पर सेल्फी लेने रुका था परिवार:

रास्ते में इंदिरा सागर बांध का नजारा देखकर परिवार जगमूर्ति सेतु के पास रुका। सभी ने फोटो खिंचवाए और सेल्फी ली। इसके बाद कार आगे बढ़ी। कुछ ही दूरी पर सामने से आए ट्रक ने टक्कर मार दी।

हादसे की सूचना मिलते ही नर्मदानगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रक जब्त कर लिया गया है। चालक ने शुरुआती पूछताछ में ब्रेक फेल होने की बात कही है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

नशे से दूरी अभियान, जिलेभर में 16 जागरूकता कार्यक्रम हुए, बुरहानपुर पुलिस ने स्कूलों, बाजारों और गांवों में शपथ, नुक्कड़ नाटक से दिया संदेश

मीडिया ऑडीटर, बुरहानपुर (निप्र)। बुरहानपुर पुलिस ने शुक्रवार को 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' अभियान के तहत जिलेभर में 16 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य नशीले पदार्थों के बढ़ते उपयोग और उसके दुष्परिणामों के प्रति आमजन, विशेषकर युवाओं को जागरूक करना था। पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान में जिले के 13 थानों और चौकियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थानों और थाना परिसरों में आयोजित किए गए। जागरूकता फैलाने के लिए ग्राम और नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों को शपथ दिलाई गई। इसके अतिरिक्त, पंपलेट वितरित किए गए, शॉर्ट मूवी दिखाई गई, नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए गए और लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रचार किया गया। प्रचार वाहनों पर पोस्टर भी चस्पा किए गए।

पंपलेट वितरित, शपथ दिलाई: कोतवाली क्षेत्र में स्थित मूक-बधिर अंध विद्यालय के बच्चों ने अपनी सांकेतिक भाषा में जिलेवासियों को नशा मुक्ति का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में भी पंपलेट वितरित किए गए और शपथ दिलाई गई। कोतवाली थाना परिसर, गणपति नाका, निंबोला, धूलकोट चौकी और नावरा चौकी पर नगर व ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों तथा कोटवारों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई। शिकारपुरा थाना क्षेत्र के आदर्श विद्यापीठ स्कूल और नेपानगर के कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। लालबाग में सागर टावर और रेलवे स्टेशन पर जनमानस को जागरूक किया गया। खकनार में नुक्कड़ नाटक का आयोजन हुआ और कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में भी कार्यक्रम किए गए।

धान रोपाई के दौरान पलटा ट्रैक्टर, नीचे दबा ड्राइवर

ग्रामीणों ने एक घंटे की मशक्कत के बाद निकाला, कीचड़ में नियंत्रण खोने से हादसा

● एक घंटे की मशक्कत के बाद निकाला बाहर

ग्रामीणों ने सामूहिक प्रयास करते हुए करीब एक घंटे तक लगातार मेहनत की। कड़ी मशक्कत के बाद चालक को ट्रैक्टर के नीचे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते सभी लोग एकजुट होकर राहत कार्य नहीं करते तो बड़ा हादसा हो सकता था। उन्होंने बताया कि सभी के सामूहिक प्रयास और सूझबूझ से चालक की जान बच गई।

मीडिया ऑडीटर, सागर (निप्र)। सागर में देवरी थाना क्षेत्र के ग्राम रामगढ़ में शनिवार को धान रोपाई के लिए खेत तैयार करते समय बड़ा हादसा हो गया। खेत में मिट्टी मचाने के दौरान ट्रैक्टर अचानक पलट गया और चालक उसके नीचे दब गया। चालक की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। समय रहते ग्रामीणों की मदद मिलने से बड़ा हादसा टल गया।

धान रोपाई के लिए तैयार किया जा रहा था खेत: जानकारी के अनुसार, देवरी के खंडेराव वार्ड निवासी ट्रैक्टर चालक देवेंद्र बैरागी शनिवार सुबह से ग्राम रामगढ़ स्थित अंकु महाराज के खेत में धान रोपाई के लिए मिट्टी मचाने का काम कर रहे थे। खेत में पानी भरा हुआ था और मिट्टी पूरी तरह दलदली हो चुकी थी।

● दलदली मिट्टी में बिगड़ा ट्रैक्टर का संतुलन

काम के दौरान अधिक पानी और दलदली मिट्टी के कारण ट्रैक्टर का संतुलन अचानक बिगड़ गया। देखते ही देखते ट्रैक्टर पलट गया और चालक देवेंद्र बैरागी उसके नीचे दब गए। हादसे के बाद खेत में अफरा-तफरी मच गई।चालक की आवाज सुनते ही आसपास काम कर रहे ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने बिना देर किए राहत कार्य शुरू किया और ट्रैक्टर को हटाने का प्रयास किया।

छतरपुर में स्कूल से लौट रहे स्टूडेंट पर हमला : ईट,लात-घूंसों से पीटा, गला दबाने का आरोप, अस्पताल में भर्ती कराया

मीडिया ऑडीटर, छतरपुर (निप्र)। छतरपुर जिले के मातगुवा थाना क्षेत्र में स्कूल से घर लौट रहे 14 वर्षीय छात्र पर दो युवकों ने रास्ता रोककर जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने छात्र को ईट, लात-घूंसों से पीटा और उसका गला भी दबाया। गंभीर रूप से घायल छात्र को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार शाम करीब 4 बजे मालगुवा निवासी आकाश यादव (14), पिता पुष्पेंद्र यादव, मामौन स्थित शासकीय स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रहा था। आरोप है कि गांव में हर्ष राजपूत और उसके छोटे भाई अंकित राजपूत ने अपने घर के सामने उसका रास्ता रोक लिया और हमला कर दिया।

बेहोश होने तक करते रहे मारपीट: परिजनों के मुताबिक, दोनों आरोपियों ने आकाश पर ईंट से वार किए, लात-घूंसों से पीटा और गला दबाने का भी प्रयास किया। मारपीट के दौरान छात्र बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे। घायल छात्र को पहले मातगुवा अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में डॉ. रोशन द्विवेदी ने छात्र का उपचार किया।

मंदसौर मेडिकल कॉलेज में पहली बार सफल सर्जरी

महिला का पैर काटकर बचाई जान, अनियंत्रित डायबिटीज से था खतरा

मीडिया ऑडीटर, मंदसौर (निप्र)। मंदसौर के सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय ने चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यहां डॉक्टरों की टीम ने पहली बार 47 वर्षीय महिला मरीज की जटिल सुप्रा मेजर सर्जरी (घुटने के ऊपर का विच्छेदन) सफलतापूर्वक कर उसकी जान बचाई। मेडिकल कॉलेज शुरू होने के बाद जिले में इस प्रकार की यह पहली बड़ी सर्जरी मानी जा रही है।

इस सफलता के साथ अब मंदसौर और आसपास के जिलों के मरीजों को ऐसे गंभीर मामलों में इंदौर, उज्जैन या अन्य बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा।

अनियंत्रित डायबिटीज बनी गंभीर बीमारी की वजह: अस्पताल के अनुसार महिला लंबे समय से अनियंत्रित मधुमेह (डायबिटीज) से पीड़ित थीं। अस्पताल पहुंचने पर उनका ब्लड शुगर स्तर लगभग 500 द्वद्द/स्द्य दर्ज किया गया, जो सामान्य स्तर से कई गुना अधिक था।

डायबिटीज के कारण उन्हें पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज (Peripheral Arterial Disease - PAD) हो गई थी। इस बीमारी में पैरों तक रक्त पहुंचाने वाली धमनियां संकरी या बंद हो जाती हैं। मरीज के बाएं पैर में रक्त प्रवाह पूरी तरह बंद हो चुका था, जिससे पैर के ऊतक धीरे-धीरे नष्ट होने लगे।

डॉप्लर जांच में सामने आई गंभीर स्थिति: डॉप्लर जांच में पता चला कि घुटने के नीचे की प्रमुख धमनियों में रक्त प्रवाह पूरी तरह बंद हो चुका था। जांच में डीप वेन थ्रॉम्बोसिस (DVT) और व्यापक एथेरोस्क्लेरोसिस की भी पुष्टि हुई।डॉक्टरों ने बताया कि मरीज का पैर नेक्रोसिस यानी ऊतकों के पूरी तरह मृत हो जाने की स्थिति में पहुंच चुका था।

● कई अस्पतालों में इलाज के बाद भी नहीं मिली राहत

परिजनों ने पहले निजी अस्पतालों और अन्य शहरों के विशेषज्ञ डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन किसी भी अस्पताल में पैर बचाने की संभावना नहीं बताई गई। इसके बाद महिला को मंदसौर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। यहां जनरल सर्जरी और मेडिसिन विभाग की संयुक्त टीम ने मरीज का इलाज शुरू किया और करीब 10 दिनों तक लगातार निगरानी में रखा।

● 10 दिन चला गहन उपचार

डॉक्टरों ने पहले मरीज की स्थिति को स्थिर करने पर ध्यान दिया। इस दौरान- डायबिटीज को नियंत्रित किया गया। संक्रमण कम करने के लिए एंटीबायोटिक उपचार दिया गया। रक्त को पतला करने वाली दवाएं दी गई। अन्य चिकित्सकीय जटिलताओं का भी इलाज किया गया। लगातार ब्लड शुगर और संक्रमण की मॉनिटरिंग की गई।

झंडू कुमार ने दिलाया भारत को पहला मेडल, पैरा पावरलिफ्टिंग में जीता ब्रॉन्ज

ग्लासगो ,एजेंसी। भारत के झंडू कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके साथ ही ग्लासगो में भारत ने मेडल टैली में अपना खाता भी खोल लिया है। दो ग्रुप वाले मुकाबले में झंडू ने 130.9 के बेस्ट रिजल्ट के साथ ग्रुप बी में टॉप किया। उन्होंने युगांडा के डेनिस म्बाजीरा (114.1) और ऑस्ट्रेलिया के बेन राइट (110.9) को आसानी से पीछे छोड़ते हुए मेडल की दौड़ में जगह बनाई। हालांकि, कंबाइंड स्टैंडिंग में नाइजीरिया के रिलुवान इदरीस ने 132.8 की बेस्ट ओवरऑल लिफ्ट के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि इंग्लैंड के मैथ्यू हार्डिंग ने 131.0 के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया। झंडू की 130.9 की लिफ्ट ब्रॉन्ज मेडल पक्का करने के लिए काफी थी। सिल्वर मेडल के लिए हुए कड़े मुकाबले में वे हार्डिंग से सिर्फ 0.1 पीछे रहे। 1 जनवरी 1997 को बिहार के नालंदा जिले के हरनौत में जन्मे झंडू जन्म से ही पोलियो से ग्रस्त थे। सब्जी बेचने वाले के बेटे झंडू एक साधारण परिवार से आते हैं, और उन्होंने दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से आर्थिक और शारीरिक चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने 2017 में पैरा-एथलीट के तौर पर अपने खेल करियर की शुरुआत की और एफ55 शॉट पुट और डिस्कस थ्रो इवेंट्स में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने कई जिला और राज्य-स्तरीय मेडल जीते। इस दौरान, जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पावरलिफ्टिंग में उनकी दिलचस्पी जगी। एक राज्य चैंपियनशिप में मिली सलाह के बाद, उन्होंने पैरा पावरलिफ्टिंग को अपना लिया।

इससे पहले दिन में, अशोक मलिक कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के लाइटवेट पैरा-पावरलिफ्टिंग इवेंट में पोडियम पर जगह बनाने से मामूली अंतर से चूक गए। उन्होंने 200 किलोग्राम की शानदार बेस्ट लिफ्ट के बावजूद 143.8 प्वाइंट्स के साथ चौथा स्थान हासिल किया। मलिक पूरे प्रतियोगिता के दौरान मेडल की दौड़ में बने रहे, लेकिन आखिर में मलेशिया के बॉनी बुन्याऊ गुस्टिन से पीछे रह गए, जिन्होंने 153.5 पॉइंट्स के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स के मौजूदा चैंपियन और इस कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर गुस्टिन भारतीय खिलाड़ी की चुनौती का सामना करते हुए पोडियम पर जगह बनाने में कामयाब रहे।

इंग्लैंड के मार्क स्वान ने 222 किलोग्राम का टॉप लिफ्ट हासिल करके 153.9 प्वाइंट्स के साथ गोल्ड मेडल जीता। नाइजीरिया के कई बार के पैरालंपिक मेडलिस्ट रोलैंड एजुरुइक प्वाइंट्स के मामले में स्वान के बराबर रहे, लेकिन काउंटबैक नियम की वजह से उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। उनका बेस्ट लिफ्ट 185 किलोग्राम था।

पुतुल सोनोवाल का शानदार प्रदर्शन जारी

फॉकलैंड आइलैंड्स के अलेक्जेंडर को हराया

ग्लासगो ,एजेंसी। भारत के टॉप लॉन बॉल्स खिलाड़ी पुतुल सोनोवाल ने ग्लासगो में पुरुषों के सिंगल्स सेक्शनल प्ले में फॉकलैंड आइलैंड्स के सेसिल अलेक्जेंडर को कड़े मुकाबले में हराकर कॉमनवेल्थ गेम्स (सीडब्ल्यूजी) 2026 में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। दोनों खिलाड़ियों के बीच हुआ मुकाबला टाई-ब्रेक तक पहुंचा, लेकिन पुतुल ने शानदार खेल दिखाते हुए जीत हासिल की। मौजूदा एशियाई चैंपियन सोनोवाल ने पहला सेट 7-5 से जीतकर बढ़त बनाई। हालांकि, सेसिल अलेक्जेंडर ने वापसी करते हुए दूसरा सेट 8-6 से जीता और मैच को टाई-ब्रेकर तक पहुंचा दिया। इसके बाद सोनोवाल ने टाई-ब्रेक 1-0 से जीतकर जीत पक्की की। भारतीय खिलाड़ी का अगला मुकाबला शनिवार को सेक्शन डी के मैच में मलेशियाई खिलाड़ी से होगा। इससे पहले गुरुवार को, सोनोवाल ने पुरुषों के सिंगल्स सेक्शनल प्ले में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन और वर्ल्ड बॉल्स हॉल ऑफ फेम में शामिल रयान बेस्टर को हराकर कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने डेब्यू पर बड़ा उलटफेर किया और बॉल्स प्रतियोगिता में भारत की शानदार शुरुआत को आगे बढ़ाया।

स्विमिंग में ऑस्ट्रेलिया ने एक ही दिन में जीते तीन गोल्ड मेडल

ग्लासगो ,एजेंसी। कॉमनवेल्थ गेम्स (सीडब्ल्यूजी) 2026 की स्विमिंग और पैरा-स्विमिंग प्रतियोगिताओं में दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया का दबदबा देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया ने कुल तीन गोल्ड मेडल अपने नाम किए, जिनमें एक पैरा-स्विमिंग का मेडल भी शामिल रहा। वहीं, साउथ अफ्रीका और मेजबान स्कॉटलैंड ने भी एक-एक गोल्ड मेडल अपने नाम किया। दिन की शुरुआत महिलाओं की 400 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा से हुई, जहां ऑस्ट्रेलिया की लानी पैलिस्टर्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता। न्यूजीलैंड की एरिका फेयरवेदर ने सिल्वर और ऑस्ट्रेलिया की जेना फॉरेस्टर ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इस जीत के साथ पैलिस्टर्स अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाते हुए मां जैनेल और गॉडमदर डॉन फ्रेजर की तरह कॉमनवेल्थ चैंपियन बनीं। जीत के बाद पैलिस्टर्स ने कहा कि यह उनके लिए बेहद खास पल है। उन्होंने कहा कि अपनी मां और डॉन फ्रेजर की तरह गोल्ड जीतना गर्व की बात है। उन्होंने अपना पहला मेडल जीतने की खुशी जताई और कहा कि प्रतियोगिता की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के लिए गोल्ड के साथ होना शानदार है। उन्होंने न्यूजीलैंड की एरिका फेयरवेदर की भी तारीफ की और कहा कि दोनों कई वर्षों से एक-दूसरे के खिलाफ मुकाबला करती आ रही हैं और हर रेस रोमांचक होती है। ऑस्ट्रेलिया की जेना फॉरेस्टर ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने महिलाओं की 200 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीत लिया। रेस के शुरुआती हिस्से में उनकी साथी तैराक हैना फ्रेडरिक्स आगे चल रही थीं, लेकिन आखिरी चरण में फॉरेस्टर ने तेजी दिखाते हुए बाजी को अपने नाम कर लिया। इससे पहले, वह 400 मीटर फ्रीस्टाइल में ब्रॉन्ज जीत चुकी थीं और उन्होंने एक ही दिन में दो मेडल अपने नाम किए। इस स्पर्धा में स्कॉटलैंड की केटी शनाहन ने सिल्वर मेडल जीतकर घरेलू दर्शकों को खुश होने का मौका दिया। खास बात यह रही कि उन्होंने उसी पूल में यह सफलता हासिल की, जहां उन्होंने तैराकी की शुरुआत की थी। पैरा-स्विमिंग में साउथ अफ्रीका के नाथन हेंड्रिक्स ने पुरुषों की 100 मीटर फ्रीस्टाइल एस13 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर बड़ा उलटफेर किया। उन्होंने मेजबान स्कॉटलैंड के पसंदीदा तैराक स्टीफन क्लेग को पीछे छोड़ते हुए साउथ अफ्रीका को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का पहला गोल्ड मेडल दिलाया।

जादुमनी का दमदार आगाज

5-0 से जीत दर्ज कर बनाई राउंड ऑफ 16 में जगह

। ग्लासगो भारत के बॉक्सर जादुमनी सिंह मंडेन्गबाम ने कॉमनवेल्थ गेम्स (सीडब्ल्यूजी) 2026 का आगाज दमदार प्रदर्शन के साथ किया है। जादुमनी ने पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में स्कॉटलैंड के एरन कलन को 5-0 से हराकर अगले दौर में जगह बना ली है ग्लासगो के एसईसी हॉल में खेले गए इस मुकाबले में जादुमनी शुरू से आखिर तक विपक्षी बॉक्सर पर पूरी तरह हावी रहे। उन्होंने तेज पंच, सटीक निशाने और मजबूत डिफेंस के दम पर अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरे मैच में वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया। सभी पांच जजों ने हर राउंड में जादुमनी को विजेता माना और उन्हें 30-27 का एक जैसा स्कोर दिया। घरेलू दर्शकों के समर्थन के बावजूद स्कॉटलैंड के एरन कलन भारतीय खिलाड़ी की गति और रणनीति के आगे बेबस नजर आए। भारतीय बॉक्सर के एक के बाद एक पंचों का एरन कलन के पास कोई जवाब नहीं था। इस जीत के साथ जादुमनी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए हैं। अब 26 जुलाई को उनका मुकाबला पाकिस्तान के रहमान से होगा। जादुमनी अगर पाकिस्तानी बॉक्सर के खिलाफ जीत दर्ज करने में सफल रहते हैं, तो वह क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल कर लेंगे। जादुमनी को भारत की ओर से पदक का बड़ा उम्मीदवार माना जा रहा है। जादुमनी की इस जीत से भारतीय बॉक्सिंग टीम ने प्रतियोगिता में मजबूत शुरुआत की है।

चिली के क्लब कोलो कोलो से जुड़ेंगे

फीफा वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले गोलकीपर वोजिन्हा

नई दिल्ली ,एजेंसी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपने शानदार प्रदर्शन से दुनिया का ध्यान खींचने वाले केप वर्डे के अनुभवी गोलकीपर वोजिन्हा अब चिली के मशहूर फुटबॉल क्लब कोलो कोलो से जुड़ने जा रहे हैं। क्लब के अध्यक्ष अनिबल मोसा ने इस समझौते की पुष्टि की है। 40 वर्षीय वोजिन्हा फिलहाल 'फ्री एजेंट' (किसी भी क्लब से अनुबंध नहीं) हैं। वह अगले कुछ दिनों में मेडिकल जांच के लिए चिली जाएंगे। मेडिकल टेस्ट पूरा होने के बाद उनके साथ आधिकारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर होंगे और फिर एस्टाडियो मॉन्यूमेंटल में उन्हें क्लब अपने नए खिलाड़ी के रूप में पेश करेगा। कोलो कोलो के अध्यक्ष अनिबल मोसा ने बताया कि वोजिन्हा जल्द ही चिली पहुंचेंगे। सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उन्हें टीम का हिस्सा बना लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन की बदौलत वोजिन्हा को यह बड़ा मौका मिला है। इसके साथ ही उन्होंने माना कि इस ट्रांसफर से क्लब को खेल के साथ-साथ व्यावसायिक स्तर पर भी फायदा मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अभी इस ट्रांसफर की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कोलो कोलो ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा कर इसके संकेत दे दिए हैं। तस्वीर में वोजिन्हा के घुंघराले बाल दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद क्लब के प्रशंसकों ने उनके आने की अटकलें तेज कर दी हैं। वर्ल्ड कप से पहले वोजिन्हा ने पुर्तगाल के दूसरे डिवीजन के क्लब चावेस को छोड़ दिया था। इसके बाद विश्व कप में अपने प्रदर्शन से वह हर किसी का दिल जीतने में सफल रहे। फीफा की फैन वोटिंग से चुनी गई वर्ल्ड कप ड्रीम टीम में भी वोजिन्हा को जगह मिली। केप वर्डे के सफल अभियान में वोजिन्हा की भूमिका बेहद अहम रही। उन्होंने चैंपियन बनी स्पेन की टीम को गोल करने से रोका और मुकाबला गोलरहित ड्रॉ पर खत्म हुआ। इसके बाद राउंड ऑफ 32 में उन्होंने अर्जेंटीना जैसी मजबूत टीम के खिलाफ भी शानदार गोलकीपिंग की और मैच को अतिरिक्त समय तक पहुंचाया। वर्ल्ड कप में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन के बाद अब वोजिन्हा को साउथ अमेरिका के सबसे सफल फुटबॉल क्लबों में से एक कोलो कोलो से जुड़ने का मौका मिला है। क्लब और उसके प्रशंसकों को उम्मीद है कि अनुभवी गोलकीपर अपने अनुभव और शानदार फॉर्म से टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे।

इतिहास रचने से एक कदम दूर अनाहत

● 21 साल का सूखा खत्म कर बनाई फाइनल में जगह

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत की अनाहत सिंह इतिहास रचने से बस एक जीत दूर हैं। मिस्र की बारब सामेह को चार गेम में हराकर वह पिछले 21 साल में वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। अपना पहला वर्ल्ड जूनियर खिताब जीतने की कोशिश में जुटीं शीर्ष वरीयता प्राप्त अनाहत 2005 में जोशना चिनप्पा के बाद फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं। उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में 3/4 सीड खिलाड़ी बारब को 11-3, 8-11, 11-4, 11-6 से हराया। अनाहत ने मजबूत शुरुआत की और पहला गेम 11-3 से जीता। इसके बाद सामेह ने वापसी की और दूसरा गेम 11-8 से जीतकर मैच बराबरी पर ला दिया। हालांकि भारतीय खिलाड़ी ने जबरदस्त वापसी की और आखिरी दो गेम 11-4 और 11-6 से जीतकर मैच को अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही उन्होंने टूर्नामेंट के फाइनल का टिकट हासिल किया, जहां उनके पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका होगा। जीत के बाद अनाहत ने कहा, 'मैं सच में बहुत खुश हूं। मैंने कुछ महीने पहले ब्रिटिश जूनियर ओपन में बारब के साथ खेला था और वह भी ऐसा ही कड़ा मुकाबला था, इसलिए मुझे पता था कि मुझे बहुत अच्छा खेलना होगा। कल मैं अपना बेस्ट नहीं खेल पाई थी और मुझे पता था कि इस मुकाबले में मुझे कोर्ट पर उतरकर दिखाना होगा कि मैं क्या कर सकती हूं। मैंने चार वर्ल्ड जूनियर टूर्नामेंट खेले हैं और क्वार्टर-फाइनल और सेमीफाइनल में हार गई थी, इसलिए फाइनल में पहुंचने से मेरे माता-पिता और कोच बहुत खुश हैं, लेकिन टूर्नामेंट अभी खत्म नहीं हुआ है।' अनाहत और ऐतिहासिक जीत के बीच अब मिस्र की दूसरी सीड खिलाड़ी रुकैया सलेम खड़ी हैं। उन्होंने फाइनल में पहुंचने के लिए अपनी ही देश की खिलाड़ी और 3/4 सीड मलिका एलकाराक्सी को हराया। पिछले साल की चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई करने में नाकाम रहीं सलेम ने शुरुआच से ही मैच पर पकड़ बनाई। उन्होंने पहले दो गेम 11-5 और 11-9 से जीते। इसके बाद सिर्फ 15 साल की एलकाराक्सी ने वापसी की और तीसरा गेम जीता, लेकिन सलेम ने अपना संयम बनाए रखा। उन्होंने एक कड़े मुकाबले वाले चौथे गेम को 11-9 से जीतकर चैंपियनशिप मैच में अपनी जगह पक्की की। मैच के बाद भावुक सलेम ने कहा, 'मेरे पास अभी कहने के लिए शब्द नहीं हैं। मैंने इस पल के लिए बहुत मेहनत की है। पिछले साल इस इवेंट के लिए क्वालीफाई न कर पाना बहुत दुखद था।

दीक्षा डागर ने कट किया पार

टूर्नामेंट में बचीं इकलौती भारतीय गोल्फर

नई दिल्ली ,एजेंसी। भारत की स्टार गोल्फर दीक्षा डागर ने महिला स्कॉटिश ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए कट पार कर लिया है। दूसरे दौर में 1 ओवर 73 का कार्ड खेलने वाली दीक्षा टूर्नामेंट में कट हासिल करने वाली इकलौती भारतीय खिलाड़ी रहीं। हालांकि, प्रणवी उर्स और अवनि प्रशांत कट हासिल करने में नाकाम रहीं और उनका अभियान दूसरे दौर के बाद ही समाप्त हो गया। पहले दौर में 74 और दूसरे दौर में 73 का स्कोर बनाने वाली दीक्षा कुल 3 ओवर पार (147) के स्कोर के साथ संयुक्त 35वें स्थान पर हैं। दूसरे राउंड में उन्होंने दूसरे, सातवें और 14वें होल पर शानदार बर्डी लगाई, लेकिन तीसरे, छठे, 13वें और 15वें होल पर बोगी के कारण कुछ शॉट गंवाने पड़े। दूसरी ओर, प्रणवी उर्स ने पहले दौर में निराशाजनक 84 का स्कोर बनाया था, लेकिन दूसरे दौर में 71 खेलकर वापसी की कोशिश की। इसके बावजूद वह कुल 11 ओवर पार के स्कोर के साथ कट से बाहर हो गईं। वहीं अवनि प्रशांत ने 80 और 77 के कार्ड खेलते हुए टूर्नामेंट से विदाई ली। दीक्षा के लिए यह प्रदर्शन बेहद अहम माना जा रहा है। लेडीज़ यूरोपियन टूर (LET) की ऑर्डर ऑफ मेरिट रैंकिंग में शीर्ष-10 में शामिल दीक्षा अगले सप्ताह होने वाले AIG वुमेंस ओपन में अपनी जगह पक्की करने के लिए इस टूर्नामेंट में मजबूत प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही हैं।

युवा सितारों पर टिकी भारत की उम्मीदें, मोहित-यशदीप-राजिंदर और लालगे दिखाएंगे दम

नई दिल्ली ,एजेंसी। एफआईएच हॉकी पुरुष वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम पूरी तरह तैयार है। बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के लिए भारत ने अनुभवी खिलाड़ियों के साथ कई युवा चेहरों को भी मौका दिया है। गोलकीपर मोहित एचएस, डिफेंडर यशदीप सिवाच और मिडफील्डर राजिंदर सिंह व आदित्य अर्जुन लालगे से टीम को बड़ी उम्मीदें होंगी। इन खिलाड़ियों ने हाल के प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का भरोसा जीता है और अब विश्व मंच पर खुद को साबित करने के लिए तैयार हैं। 23 वर्षीय मिडफील्डर आदित्य अर्जुन लालगे ने कहा कि वर्ल्ड कप में खेलना उनका बचपन का सपना रहा है और अब उनका पूरा ध्यान टीम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने पर है। उन्होंने कहा कि सीनियर खिलाड़ियों और कोचों का लगातार मार्गदर्शन उन्हें आत्मविश्वास देता है और पूरी टीम एक ही लक्ष्य के साथ मेहनत कर रही है। मिडफील्डर राजिंदर सिंह ने टीम की एकजुटता को सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी मैदान के अंदर और बाहर एक-दूसरे का पूरा साथ देते हैं और कोई गलती होने पर साथी खिलाड़ी तुरंत मदद के लिए तैयार रहता है। यही टीम स्पिरिट भारत को मजबूत बनाती है। डिफेंडर यशदीप सिवाच ने बताया कि वर्ल्ड कप की तैयारियां बेहद कड़ी रही हैं। फिटनेस, तकनीक और रणनीति के हर पहलू पर काम किया गया है। उन्होंने कप्तान हरमनप्रीत सिंह, जरमनप्रीत सिंह और अमित रोहिदास जैसे अनुभवी खिलाड़ियों से मिले मार्गदर्शन को अपने विकास में अहम बताया। गोलकीपर मोहित एचएस ने कहा कि पिछला वर्ल्ड कप उन्होंने बेंगलुरु में जूनियर राष्ट्रीय शिविर से देखा था और तभी सपना देखा था कि एक दिन भारत के लिए इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। उन्होंने कहा कि जूनियर वर्ल्ड कप से लेकर अब तक उनके खेल में काफी निखार आया है और वह कोचों व सीनियर खिलाड़ियों से लगातार सीखते रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का संतुलन टीम को मजबूत बनाएगा। भारत को वर्ल्ड कप में पूल डी में रखा गया है। टीम अपना पहला मुकाबला 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को पाकिस्तान से भिड़ेगी। भारतीय टीम की नजरें 51 साल बाद हॉकी विश्व कप खिताब जीतने पर होंगी।

जमीन पर बैठकर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सुनी ग्रामीणों की बात, करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की दी सौगात

छत्तीसगढ़ सरकार गांवों के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रही-उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज कबीरधाम जिले के अपने विधानसभा क्षेत्र के सहसपुर लोहारा विकासखंड अंतर्गत ग्राम भेंड्रा नवागांव और पीरचाटोला में आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रमों में शामिल होकर ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में ग्रामीणों के बीच जमीन में बैठकर उनकी समस्याएं और मांगें सुनीं तथा कई मांगों पर मौके पर ही स्वीकृति और घोषणाएं करते हुए विकास कार्यों की सौगात दी। उप मुख्यमंत्री ने ग्राम भेंड्रा नवागांव में आयोजित कार्यक्रम से ग्राम बोटेसुर से नवागांव तक एक करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सड़क निर्माण कराने की घोषणा की। वहीं ग्राम पीरचाटोला में 5.20 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण तथा वीबीजीरामजी योजना के तहत पुलिया निर्माण का प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृत कराने की घोषणा की।ग्रामीणों को संबोधित करते हुए

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार गांवों के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है और विकास कार्यों के लिए निरंतर स्वीकृति दी जा रही है। उन्होंने बताया कि भेंड्रा नवागांव, बोटेसुर के गांवों में सामुदायिक भवन, सीसी रोड, बोर खनन, रंगमंच, आहता निर्माण तथा आंतरिक विद्युतीकरण जैसे अनेक कार्य पूरे किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि सूरजपुरा पंचायत में 51 लाख रुपये की लागत से मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक स्टेडियम में नियमित खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हों तथा आसपास के 15 से 20 गांवों के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि युवाओं को सकारात्मक दिशा मिल सके। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सूरजपुरा और धनौरा सहित क्षेत्र में कई सड़कों का निर्माण कराया गया है। उन्होंने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी विकास कार्य गुणवत्तापूर्ण मानको के अनुरूप होना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि पीरचाटोला में 40, सूरजपुरा में 57, पेण्ड्रातराई में 61, बैगापारा में 65 तथा बोटेसुर में 75 आवास स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के गठन के बाद पहली ही कैबिनेट बैठक में 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी गई थी और बीते ढाई वर्षों में 11 लाख आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिला स्व-सहायता समूह डेयरी, दुग्ध उत्पादन और अन्य स्वरोजगार गतिविधियों से जुड़कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। यदि समूह कार्ययोजना बनाकर आगे आते हैं तो शासन हर संभव सहयोग करेगा। उन्होंने क्षेत्र में जैविक खेती की व्यापक संभावनाओं का उल्लेख करते हुए किसानों को प्राकृतिक एवं जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि केवल भवन और सड़क निर्माण ही विकास नहीं है, बल्कि गांव की आर्थिक गतिविधियों, कृषि, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने बस्तर, कोंडागांव और नारायणपुर के वनांचल क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां किसान बिना रासायनिक खाद के सफलतापूर्वक जैविक खेती कर रहे हैं और बेहतर आय अर्जित कर रहे हैं।

आंगनबाड़ी केंद्रों में गुणवत्ता एवं मानक अनुरूप पोषण आहार उपलब्ध, सुरहूलखास मामले में जांच में तथ्य स्पष्ट

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। विभिन्न माध्यमों में बलरामपुर जिले के सुरहूलखास आंगनबाड़ी केंद्र में एक्सपायरी डेट का रेडी-टू-ईट (आरटीई) पोषण आहार बच्चों को वितरित किए जाने संबंधी प्रसारित समाचारों के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तत्काल जांच कराई गई। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि बच्चों को किसी भी प्रकार का एक्सपायरी डेट का पोषण आहार वितरित नहीं किया गया तथा उन्हें उपयोग अवधि के भीतर का गुणवत्ता एवं मानक अनुरूप पूरक पोषण आहार ही उपलब्ध कराया गया। विभागीय अधिकारियों द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, हितग्राहियों एवं ग्राम प्रतिनिधियों से चर्चा की गई। जांच में पाया गया कि केंद्र में बच्चों को वितरित किया गया शिशु शक्ति रेडी-टू-ईट आहार पूरी तरह सुरक्षित था तथा उसकी उपयोग अवधि शेष थी। सभी बच्चे एवं हितग्राही स्वस्थ पाए गए तथा किसी भी प्रकार की खाद्यजनित समस्या अथवा प्रतिकूल प्रभाव का कोई मामला सामने नहीं आया। निरीक्षण के दौरान केंद्र में उपलब्ध रेडी-टू-ईट के दो पैकेट, जो शिशुवती माताओं के लिए निर्धारित थे, उनकी उपयोग अवधि समाप्त हो चुकी थी। विभाग ने स्पष्ट किया कि इन पैकेटों को वितरण से पूर्व ही नियमानुसार विनष्टीकरण (डिस्पोजल) हेतु पृथक एवं सुरक्षित रखा गया था। इनका बच्चों अथवा अन्य हितग्राहियों के बीच वितरण नहीं किया गया। जांच के दौरान ग्राम के उप सरपंच सहित स्थानीय हितग्राहियों ने भी बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को नियमित रूप से ताजा एवं निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप रेडी-टू-ईट पोषण आहार उपलब्ध कराया जाता है तथा केंद्र की गतिविधियां सुचारु रूप से संचालित हो रही हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग ने कहा है कि प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं, शिशुवती माताओं तथा 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को निर्धारित गुणवत्ता एवं मानकों के अनुरूप पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है।

वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देश पर वन अपराधों की जांच प्रक्रिया को बनाया जा रहा अधिक प्रभावी

वन अधिकारियों और मैदानी अमले को ऑनलाइन पीओआर एवं वन अपराध जांच प्रक्रिया का प्रशिक्षण

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार वन अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण, जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता और विभागीय कार्यों में तेजी लाने के लिए वन विभाग द्वारा ऑनलाइन प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। इसी क्रम में वनमंडल दंतेवाड़ा में वन अधिकारियों एवं मैदानी अमले के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।ऑनलाइन पीओआर और जांच प्रक्रिया पर दिया गया प्रशिक्षण प्रशिक्षण में ऑनलाइन पीओआर यानी प्रारंभिक अपराध रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही जांच अधिकारी की नियुक्ति, जप्त वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में

की जाने वाली कार्रवाई, न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने तथा आवश्यक प्रपत्र तैयार करने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया। अधिकारियों ने प्रतिभागियों को वन अपराध प्रकरणों की जांच के दौरान उप वनमंडलाधिकारी, वनमंडलाधिकारी और मुख्य वन संरक्षक स्तर तक प्रकरण प्रस्तुत करने एवं अग्रेषित करने की प्रक्रिया समझाई। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों ने प्रतिभागियों की शंकाओं का समाधान करते हुए वन अपराध प्रकरणों के त्वरित और विधिसम्मत निराकरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ेगी प्रशिक्षण में बताया गया कि ऑनलाइन प्रणाली के प्रभावी उपयोग से वन अपराध प्रकरणों की निगरानी और निराकरण में तेजी आएगी। इससे विभागीय कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता भी बढ़ेगी। अधिकारियों ने सभी मैदानी अमले से प्रशिक्षण में प्राप्त जानकारी का क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का आह्वान किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में वनमंडलाधिकारी श्री रंगनाथ रामाकृष्णावाय.,उप वनमंडलाधिकारी दंतेवाड़ा, उप वनमंडलाधिकारी गीदम सहित वनमंडल दंतेवाड़ा के सभी परिक्षेत्र अधिकारी और मैदानी अमले के अधिकारी- कर्मचारी उपस्थित रहे।

एक पेड़ माँ के नाम 3.0' से हरित भविष्य का संकल्प होगा और मजबूत : वनमंत्री केदार कश्यप

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप आज जगदलपुर स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में आयोजित जिला स्तरीय वन महोत्सव 2026 और 'एक पेड़ माँ के नाम 3.0' अभियान में शामिल हुए। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, विद्यार्थियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का सामूहिक संकल्प लिया।पौधारोपण ही भविष्य का संकल्प वनमंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि पौधारोपण केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य का संकल्प है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान प्रकृति और मातृत्व के प्रति हमारी

भावनाओं को मजबूत करता है। उन्होंने नागरिकों से पौधे लगाने के साथ-साथ उनके संरक्षण की जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया। इसके बाद 'ग्रीन कैनवास' अभियान के तहत वनमंत्री सहित जनप्रतिनिधियों और अतिथियों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए हस्ताक्षर किए। 630 पौधों को गोद लेकर उनके संरक्षण की जिम्मेदारी ली भारत स्काउट्स एवं गाइड्स जिला संघ बस्तर ने रोपे गए सभी 630 पौधों को गोद लेकर उनके संरक्षण की जिम्मेदारी ली। वनमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि पौधारोपण तभी सफल होगा जब लगाए गए पौधे सुरक्षित रहकर बड़े वृक्ष बनें और आने वाली पीढ़ियों को छाया, शुद्ध हवा और जीवन प्रदान करें। हितग्राहियों को मिली आर्थिक सहायता कार्यक्रम में वन विभाग की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को 35.98 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि और डमी चेक वितरित किए गए। लाभार्थियों में तेंदूपत्ता संग्राहक कल्याण योजना, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मालिक मकबूजा योजना, किसान वृक्ष मित्र योजना और मानव-वन्यप्राणी द्वंद्व राहत योजना के हितग्राही शामिल रहे। इस अवसर पर बस्तर सांसद श्री महेश कश्यप, जगदलपुर विधायक श्री किरण सिंह देव, चित्रकोट विधायक श्री विनायक गोयल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप, महापौर श्री संजय पांडेय सहित जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी, इंजीनियरिंग कालेज परिवार के सदस्यों, वन विभाग के कर्मचारी और पर्यावरण संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

स्काउट्स एवं गाइड्स की गतिविधियों को प्रभावी बनाने राज्य मुख्य आयुक्त ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के राज्य मुख्य आयुक्त श्री इंदरजीत सिंग खालसा की अध्यक्षता में जिला संगठन आयुक्तों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन की गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। राज्य मुख्य आयुक्त ने निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी विद्यालयों में प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगीत का गायन अनिवार्य रूप से कराया जाए तथा संगठन के अंशदान की राशि 31 अगस्त तक अनिवार्य रूप से जमा कराई जाए।स्काउट-गाइड गतिविधियों की जिले में होगी समीक्षा भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ के राज्य मुख्य आयुक्त ने कहा

कि प्रत्येक विद्यालय में स्काउट-गाइड दलों के प्रभावी संचालन के लिए कम से कम एक प्रशिक्षित बेसिक स्काउट मास्टर एवं एक गाइड कैप्टन का होना आवश्यक है। साथ ही राज्य स्तर से प्रत्येक जिले का नियमित दौरा कर स्काउट-गाइड गतिविधियों की समीक्षा किए जाने की जानकारी भी दी। व्यापक वृक्षारोपण अभियान आयोजित करने के निर्देश बैठक में ओवायएमएस (OYMS) पंजीयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक जिले में कार्यशालाओं के आयोजन तथा प्रत्येक विकासखंड में एक-एक समन्वयक (कोऑर्डिनेटर) नियुक्त करने के निर्देश दिए गए, ताकि पंजीयन की प्रक्रिया समयबद्ध एवं सुचारु रूप से पूर्ण की जा सके। इसके साथ ही प्रत्येक जिला एवं विकासखंड स्तर पर व्यापक वृक्षारोपण अभियान आयोजित करने के निर्देश देते हुए इसमें समाज एवं जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। स्काउट-गाइड स्वयंसेवक राहत एवं बचाव कार्यों में करेंगे सहयोग संभावित बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य मुख्य आयुक्त ने सभी जिला संगठन आयुक्तों को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) एवं राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के साथ समन्वय बनाए रखने तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर स्काउट-गाइड स्वयंसेवक राहत एवं बचाव कार्यों में जिला प्रशासन का सहयोग करने के लिए सदैव तैयार रहें।

बैठक के दौरान राज्य मुख्य आयुक्त श्री इंदरजीत सिंग खालसा को राष्ट्रीय वयस्क स्काउटिंग समिति का सदस्य मनोनीत किए जाने पर पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका सम्मान किया गया। बैठक के अंत में उन्होंने सभी जिला संगठन आयुक्तों से संगठन की गतिविधियों को अधिक प्रभावी, अनुशासित एवं सेवा-भावना के साथ संचालित करने का आह्वान किया। बैठक में राज्य प्रशिक्षण आयुक्त श्री पूनम सिंह साहू, राज्य संगठन आयुक्त श्री अमित कुमार, राज्य संगठन आयुक्त (गाइड) श्रीमती जलवती साहू, राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (गाइड) श्रीमती सरिता पाण्डेय, राज्य संयुक्त सचिव श्रीमती बीना यादव सहित राज्य कार्यालय के पदाधिकारी उपस्थित थे।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने वन महोत्सव का किया शुभारंभ

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। पर्यावरण संरक्षण को जनभागीदारी से जनआंदोलन बनाने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान 3.0 का शुभारंभ लोरमी विकासखण्ड के ग्राम बैगाकापा में किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कल्पवृक्ष का पौधा लगाकर पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश दिया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता फैलाने 'वृक्ष मित्र वाहन' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन गॉवों-शहरों में जाकर नीबू, मुनगा, बिही, जामुन आदि के पौधे वितरित कर नागरिकों को पौधारोपण के लिए प्रोत्साहित करेगी।उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यक्रम में कहा कि जलवायु परिवर्तन आज वैश्विक चुनौती है और इससे निपटने के लिए वृक्षारोपण के साथ वर्षा जल का संरक्षण भी अत्यंत आवश्यक है। प्रकृति के संतुलन के लिए पेड़, पानी और पर्यावरण का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन की चुनौती का उल्लेख करते हुए अधिक से अधिक वृक्षारोपण तथा वर्षा जल के संरक्षण के लिए प्रेरित किया, ताकि ग्रीष्मकाल में जल संकट से बचा जा सके। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, ग्रामीणों एवं बड़ी संख्या में नागरिकों ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम में परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार, वनमंडलाधिकारी श्री अभिनव कुमार, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री श्रीकांत पाण्डेय और जिला पंचायत के सीईओ श्री गोकुल रावटे के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि, वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, ग्रामीणजन और स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

प्राकृतिक आपदा के पांच मामलों में मृतकों के परिजनों को 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। जशपुर जिले में प्राकृतिक आपदा एवं आकस्मिक जनहानि के पांच मामलों में प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करते हुए कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने राजस्व पुस्तक परिपत्र (आर.बी.सी.) 6-4 के तहत कुल 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। प्रत्येक प्रकरण में मृतक के निकटतम वैध वारिस को 4 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता प्रदान की जाएगी। अपर कलेक्टर श्री प्रदीप साहू से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मनोरा तहसील के ग्राम अंधला निवासी स्व. जोसेफ की नाले में डूबने से हुई मृत्यु के मामले में उनके पुत्र सामृत मिंज को 4 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार बागबहार तहसील के ग्राम मुड़ाबहला निवासी स्व. निखिल सिदार की तालाब (डबरी) में डूबने से हुई मृत्यु के मामले में उनके पिता फतेराम को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। पत्थलगांव तहसील के ग्राम पत्थलगांव निवासी स्व. राजवंती देवी साहू की नदी में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पति बिन्देश्वरी साहू को 4 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। कांसाबेल तहसील के ग्राम बटईकेला निवासी स्व. दुर्योधन राम की कुएं में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी श्रीमती दिलासो बाई को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। वहीं, कुनकुरी तहसील के ग्राम घटमुण्डा नवाटोली निवासी स्व. एलड्रिन एक्का की आग से झुलसने के कारण हुई मृत्यु के मामले में उनके पिता प्रबोध एक्का को 4 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत की गई है। जिला प्रशासन द्वारा प्राकृतिक आपदा एवं आकस्मिक जनहानि के मामलों में प्रभावित परिवारों को समयबद्ध राहत उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाएं प्राथमिकता के साथ पूरी की जा रही हैं, ताकि संकट की घड़ी में उन्हें शीघ्र आर्थिक संबल मिल सके।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता कोरबाप्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अपनाकर मंत्री श्री लखनलाल देवांगन बने सौर ऊर्जा के प्रेरक

स्वच्छ एवं हरित भविष्य के लिए नागरिकों को किया प्रेरित

मीडिया ऑडीटर, रायपुर (निप्र)। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने वाली इस योजना के माध्यम से कोरबा जिले के अनेक परिवार स्वच्छ ऊर्जा को अपनाते हुए बिजली उपभोक्ता से ऊर्जा उत्पादक बनने की दिशा में अग्रसर हैं। इससे उन्हें बिजली बिल में उल्लेखनीय बचत होने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देने का अवसर मिल रहा है। इसी क्रम में प्रदेष के उद्योग, वाणिज्य, श्रम एवं आबकारी मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने भी अपने कोहड़िया स्थित निवास पर योजना के अंतर्गत 10 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित कराया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने तथा पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से उन्होंने अपने

निवास पर सोलर संयंत्र स्थापित कराया है। मंत्री श्री देवांगन ने बताया कि सोलर पैनल स्थापित हुए लगभग एक माह हो चुका है और इसके सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। इससे न केवल आर्थिक बचत हो रही है, बल्कि स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के उपयोग से पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी के कारण सोलर संयंत्र स्थापित करना आम नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक और लाभकारी बन गया है। उन्होंने बताया कि घरेलू उपयोग के बाद बची हुई अतिरिक्त बिजली विद्युत वितरण कंपनी के ग्रिड में भेजी जाएगी, जिससे भविष्य में अतिरिक्त आय प्राप्त होने की भी संभावना रहेगी। मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने प्रदेश एवं कोरबा जिले के नागरिकों से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना केवल एक योजना नहीं, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता का जनआंदोलन है। यह लोगों को केवल बिजली उपभोक्ता नहीं, बल्कि ऊर्जा उत्पादक बनने का अवसर प्रदान कर रही है। उन्होंने नागरिकों से सोलर ऊर्जा अपनाकर स्वच्छ, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भविष्य के निर्माण में सहभागी बनने का आह्वान किया। उन्होंने इस जनकल्याणकारी पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता के कारण प्रदेश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को नई गति मिल रही है।

स्वत्वाधिकारी मुद्रक / प्रकाशक संदीप द्विवेदी द्वारा विप्र एक्सप्रे प्रेस सीपत रोड सरकंडा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुद्रित कर मीडिया ऑडीटर कार्यालय वार्ड 14 हल्दीबाड़ी एमसीबी छत्तीसगढ़ से प्रकाशित,संपादक संदीप द्विवेदी
आर .एन .आई नं . सी टी एच आई एन /25/ए 1478 फोन नं .7974467831,9589645803, mediaauditor1@gmail .com पीआइबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार , सभी विवादों का न्याय क्षेत्र रीवा होगा